RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

हमें कभी भी अपनी जड़ें भूलनी नहीं चाहिए। हम जिस जगह से आते है उस पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए।

रतन टाटा

वर्ष-07, अंक - 40 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 26 जून 2025 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

19 इंच से ज्यादा बारिश, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

नई दिल्ली, एजेंसी।

देशभर में मानसून की दस्तक के साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गुजरात, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सूरत में 36 घंटे में 19 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे शहर का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, वहीं जम्मू में एक व्यक्ति को एसडीआरएफ ने बाढ़ से बचाया।

गुजरात के सूरत शहर में बीते 36 घंटों में 19 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। कई आवासीय क्षेत्रों में पानी घरों के अंदर तक घुस गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रभावित लोगों को ट्रैक्टर और नावों की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने सूरत समेत कच्छ क्षेत्र में यलो अलर्ट और अन्य हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। अस्पताल से घर लौट रहा एक परिवार उस समय हादसे का शिकार हो गया जब उनकी कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन दिन पहले जन्मा नवजात भी शामिल है। कार में कुल सात लोग सवार थे, जिनमें से तीन गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते नहर उफान पर थी और दृश्यता कम होने के कारण चालक को मोड़ का अंदाजा नहीं लग सका।

जम्मू में तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण एक व्यक्ति पानी में फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना एसडीआरएफ को दी। टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर रस्सी और सीढ़ियों की मदद से व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों की नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे अचानक बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश से भी भारी बारिश के कारण 12 लोगों की मौत की सूचना है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। इस बीच दिल्ली में भी मौसम विभाग ने आज के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर, मानसून ने चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है और अगले दो दिनों में इसके पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है।

आपातकाल के 50 सालः प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया लोकतंत्र का काला अध्याय

नई दिल्ली, एजेंसी।

आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 1975 को लागू की गई उस ऐतिहासिक घटना को याद किया जिसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म %एक्स% पर एक के बाद एक पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उस दौर की यादें साझा कीं।

प्रधानमंत्री ने लिखा कि जब आपातकाल लगाया गया था, तब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक युवा प्रचारक थे। उन्होंने बताया कि आपातकाल विरोधी आंदोलन उनके लिए एक बड़ा सीखने का अनुभव था, जिसने लोकतांत्रिक ढांचे की अहमियत को और मजबूती से समझने का अवसर दिया।

मोदी ने बताया कि ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने आपातकाल से जुड़े अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया है, जिसकी प्रस्तावना एच. डी. देवेगौड़ा ने लिखी है। देवेगौड़ा स्वयं भी आपातकाल विरोधी आंदोलन में सक्रिय रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 को भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी और बड़ी संख्या में राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेलों में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था।

प्रधानमंत्री ने 'द इमरजेंसी डायरीज' पुस्तक का उल्लेख करते हुए बताया कि इसमें आपातकाल के दौरान की उनकी यात्रा का वर्णन है, जो उस समय की कई घटनाओं को पुनः जीवंत कर देती है। उन्होंने आग्रह किया कि वे लोग जिन्होंने आपातकाल के दौरान कष्ट झेले हैं या जिनके परिवार इससे प्रभावित हुए थे, वे अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करें ताकि नई पीढ़ी को उस दौर की सच्चाई का ज्ञान हो सके।

प्रधानमंत्री ने लिखा कि वह उन सभी लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के कोने-कोने से आए लोगों का सामूहिक प्रयास था, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य किया। यही वह संघर्ष था जिसके चलते तत्कालीन सरकार को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े, जिनमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा।

आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर केंद्र का प्रस्ताव, कांग्रेस ने साधा निशाना

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले पीड़ितों को श्रद्धांजलि स्वरूप दो मिनट का मौन रखा गया।

इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली चरम पर है, लेकिन सरकार के पास इन समस्याओं का कोई जवाब नहीं है। इसलिए यह लोग अपने झूठ को छिपाने के लिए नाटक कर रहे हैं और संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं।

खड़गे ने कहा कि जो लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जिनका न तो स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान रहा और न ही संविधान निर्माण में। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां जलाई थीं और यह कहा था कि इस संविधान में हमारी पारंपरिक संस्कृति और मनुस्मृति के तत्व शामिल नहीं हैं, इसलिए वे इसे नहीं मानते।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों से देश में एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने एक परिपत्र जारी कर सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए।

खड़गे ने कहा कि जो लोग अब संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वे केवल बीते हुए एक पुराने मुद्दे को फिर से उछालने की कोशिश कर रहे हैं। जिनका न भारत की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान था और न संविधान निर्माण में, वे अब इस पर राजनीति कर रहे हैं।

जस्टिस मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं?

नई दिल्ली, एजेंसी।

सरकारी आवास पर बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिलने के मामले में घिरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा का विषय मंगलवार को संसद की स्थायी समिति की बैठक में भी उठा। समिति के सदस्यों ने सख्त सवाल उठाते हुए पूछा कि अभी तक इस गंभीर मामले में कोई प्राथमिकी (एफआईआर) क्यों दर्ज नहीं की गई।

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान कई सदस्यों ने %वीरस्वामी मामले% की दोबारा समीक्षा की मांग की, जिसमें न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इसके अलावा समिति ने न्यायाधीशों के लिए एक स्पष्ट आचार संहिता बनाए जाने तथा सेवा निवृत्ति के बाद किसी भी पद को ग्रहण करने से पहले ÷शीतकालीन-अवधि÷ (कूलिंग ऑफ पीरियड) निर्धारित करने का सुझाव दिया।

यह चर्चा ऐसे समय में हुई है जब संसद के आगामी मानसून सत्र में न्यायाधीश वर्मा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं।

राज्यसभा की इस समिति की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजलाल कर रहे हैं। समिति में भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई (जो मनोनीत सांसद हैं), पूर्व विधि राज्यमंत्री पी पी चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय और कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के विवेक तन्खा तथा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद पी विल्सन और ए राजा प्रमुख सदस्य हैं।

बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने यह भी सवाल उठाया कि न्यायाधीशों के लिए बने 16 बिंदुओं वाले आचार संहिता का पालन क्यों नहीं हो रहा। यह आचार संहिता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 में लागू की गई थी। सांसदों का कहना था कि यह संहिता अब केवल कागजों तक सीमित रह गई है।

साल 2023 में यह सिफारिश की गई थी कि न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए, लेकिन इसका पालन भी अधूरा ही है।

सरकारी स्कूलों में अब पढ़नी होंगी ममता बनर्जी की किताबें, मचा राजनीतिक बवाल

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश के अनुसार, अब सभी सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लिखित 19 किताबें पुस्तकालयों में रखी जाएंगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को यह किताबें अनिवार्य रूप से खरीदने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

भाजपा नेता अमित मालवीय ने इसे करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि तृणमूल सरकार शिक्षा के नाम पर प्रचार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों को ममता बनर्जी की ÷बेतुकी रचनाओं÷ से दंडित किया जा रहा है। वहीं शिक्षक संगठनों ने भी इसका विरोध करते हुए आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस फैसले को हिटलरशाही÷ करार दिया और कहा कि जब स्कूलों के पास चॉक-डस्टर खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तब किताबें थोपना जनता के पैसों की लूट है। उन्होंने कटाक्ष किया कि ये किताबें पन्ने फाड़कर ठोंगा बनाने लायक भी नहीं हैं।

इस फैसले को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार किताबें थोप सकती है और क्या यह छात्रों के हित में है।

सीबीएसई 2026 से साल में दो बार लेगा 10वीं की बोर्ड परीक्षा

नई दिल्ली।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्ष 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित करने के नियमों को स्वीकृति दे दी है। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने दी। नई व्यवस्था के तहत पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी परीक्षा मई में कराई जाएगी।

पहली परीक्षा में शामिल होना छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, जबकि दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी। आंतरिक मूल्यांकन पूरे सत्र में केवल एक बार ही किया जाएगा।

इस निर्णय से छात्रों को अपने अंकों में सुधार का अवसर मिलेगा। यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है तो वह दूसरी परीक्षा में शामिल होकर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकेगा।

छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी तीन विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधारने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, शीतकालीन सत्र वाले विद्यालयों के छात्र किसी भी एक चरण में परीक्षा दे सकेंगे।

सीबीएसई ने इस वर्ष फरवरी में इन नियमों का प्रारूप जारी किया था और फिर इसे सार्वजनिक राय के लिए आमंत्रित किया गया था। यह निर्णय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य बोर्ड परीक्षा के दबाव को कम करना और छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करना है।

भारतीय गगनयात्री ने रचा इतिहास, बने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारत के लिए 25 जून का दिन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया। भारतीय वायुसेना के समूह कप्तान शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम मिशन-4 के तहत अंतरिक्ष की ओर सफलतापूर्वक उड़ान भरी। यह मिशन नासा और इसरो के साझा सहयोग से संचालित हुआ है। शुभांशु ने अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे प्रक्षेपण यान के माध्यम से उड़ान भरी। उनके साथ तीन अन्य अंतरिक्ष यात्री भी इस अभियान का हिस्सा हैं।

शुभांशु शुक्ला स्पेस एक्स के फाल्कन-9 प्रक्षेपण यान से जुड़े ड्रैगन यान में सवार होकर रवाना हुए। लगभग 28.5 घंटे की यात्रा के बाद यह यान 26 जून को शाम 4:30 बजे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ेगा। इस मिशन के माध्यम से शुभांशु अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले केवल राकेश शर्मा ने वर्ष 1984 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा की थी। उनके बाद 41 वर्षों में यह पहला अवसर है जब एक भारतीय नागरिक ने दोबारा अंतरिक्ष में कदम रखा है।

इस ऐतिहासिक मिशन को अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में कई तकनीकी और प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। 29 मई को यान की तैयारी अधूरी होने के कारण उड़ान टली। 8 जून को प्रक्षेपण यान में तकनीकी समस्या आई। 10 और 19 जून को खराब मौसम और अंतरिक्षयात्रियों की सेहत के कारण प्रक्षेपण को स्थगित किया गया। 11 जून को ऑक्सीजन रिसाव की समस्या सामने आई, जबकि 22 जून को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के सेवा खंड की अतिरिक्त जांच की आवश्यकता पड़ी। इन सभी अड़चनों को पार करते हुए आखिरकार 25 जून को शुभांशु शुक्ला का मिशन सफलतापूर्वक प्रारंभ हुआ।

यह उपलब्धि न केवल भारत के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह हमारे वैज्ञानिक कौशल, तकनीकी प्रगति और वैश्विक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी का प्रमाण भी है।

प्रशासन हकीकत सामने लाए न कि लीपा पोती कर इतिश्री करें...

पथवारी वाले इस कुप से सप्लाई हुए पानी पिने से बिमार हुए लोग-ग्रामीण।

उल्टी-दस्त से बिमार ग्रामीण 5 दिन बाद भी पहुच रहे अस्पताल।

माही की गूंज, खवासा/भामल।

अहमदाबाद में हुए भयानक विमान हादसे के बाद सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का बयान आया कि, यह एक घटना थी और इसे रोका नहीं जा सकता।

अगर घटना को रोका नहीं जा सकता है तो उससे सबक तो लिया जा सकता है। उसके कारण की जाच तो की जा सकती है जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित न हो। लेकिन आमतौर पर यह देखने में आता है कि, प्रशासन किसी भी घटना के घटित हो जाने के बाद केवल अपना दामन बचाने के लिए लीपा पोती में जुट जाता है और मामले को खत्म करने का प्रयास किया जाता है।

कुछ ऐसा ही मामला झाबुआ जिले के ग्राम भामल में एक साथ दर्जनों व्यक्तियों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और मरीजों को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया। यही नहीं भामल की स्कूल में भी मरीजो का उपचार प्रशासनिक अमले द्वारा उपचार मुहेया कराया गया। प्रशासनिक अमले की इस त्वरित और मानवीय कार्यवाही के लिए निश्चित रूप से प्रशासन बधाई का पात्र है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए प्रशासन को चाहिए था कि, वो मामले की बारीक जांच पड़ताल कर इस सामूहिक बीमारी के कारणों का पता लगाए। लेकिन पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारी अपना दामन बचाते नजर आए और घटना को एक सामूहिक भोज के कारण को बतलाकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है।

क्या है मामला

गत दिनों 21 जून को रात्रि में भामल के कई नागरिकों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई रात्रि में ही ये लोग पेटलावद के अस्पताल में इलाज हेतु गए और सुबह में अन्य कई लोगों को इसी प्रकार की शिकायत हुई। जिसके बाद प्रथम दृष्टिया मामला दूषित पेयजल का लगा जिसको पीने के बाद लोग बीमार हुए। लेकिन प्रशासनिक अमले के हरकत में आने के बाद प्रशासन ने घटना के कारण को पेयजल नहीं माना लेकिन कुए के पानी की जांच करवाई गई जिसमें पानी को पीने योग्य माना गया।

लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि, घटना वाले दिन ही प्रशासन ने पंचायत प्रतिनिधि को कह कर पूरे कुए का पानी खाली करवा दिया था और एक अन्य निजी नलकूप का पानी कुएं में डाला गया था। ऐसे कुएं के पानी, नलकूप के पानी की जांच प्रशासन द्वारा करवाई गई और नलकूप के पानी की रिपोर्ट नार्मल आई है न कि कुए के पानी की...! वहीं प्रशासन ने इस घटना को जिम्मेदार गांव में एक व्यक्ति नाहरसिंह लाला जी खेर (60) की मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्तियों के लिए बनाए गए खाने को बताया गया। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि, उस खाने में अधिकतर बाहर के लोगों ने खाना खाया था और जिन व्यक्तियों ने उस खाने को खाया वो बीमार ही नहीं हुए। ऐसे में प्रशासन का यह दावा की दूषित खाने को खाने से लोग बीमार हुए, स्थानीय जनता को रास नहीं आ रहा है।

वहीं ग्रामीणों का कहना है कि, गांव में कई वाल्व लगे हैं और वे खुले हैं। हो सकता है उनमें से गंदगी रिस कर लोगों के घरों में पहुंच गई होगी और वे बीमार हुए! बरहाल घटना के कारण की सुक्ष्म जाँच आवश्यक है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोका जा सके। साथ ही खवासा पंचायत को भी चाहिए कि वो भामल की घटना से सबक लेकर अपनी व्यवस्था दुरुस्त करें। नही तो खवासा में भी कई वाल्व खुले पड़े हैं और इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है।

नगर की ट्रैफिक व्यवस्था फिर से चरमराई, सब्जी और फल विक्रेताओं के हटने के बाद हुआ समस्या का समाधान

माही की गूंज, बामनिया।

ग्राम के मुख्य चौराहे पर हमेशा यातायात का दबाव रहता है जिसका मुख्य कारण रेलवे क्रासिंग है जहां पर थोड़ी-थोड़ी देर में फाटक बंद होने से दोनों ओर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है और फाटक खुलने पर एक साथ वाहन मुख्य मार्ग चौराहे पर पहुँच जाते हैं। मुख्य चौराहे पर काफी कम जगह होने के कारण जाम स्थिति निर्मित हो जाती है। ग्राम की इस बड़ी समस्या से निजाद पाने के लिए ग्राम पंचायत ने बड़ी पहल करते हुए मुख्य मार्ग पर बैठे सब्जी और फल विक्रेता को अन्य जगह स्थान परिवर्तन कर भेज दिया। जिससे काफी हद तक इस समस्या से ग्रामवासियों को निजाद मिल गई थी। साथ ही मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छी हो गई थी। समय के साथ कई फल और सब्जी विक्रेता अपनी अस्थाई दुकाने लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर मुख्य चौराहे, नारेला रोड , रतलाम रोड पर खड़े होने लग गए जिससे एक बार फिर ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होने लग गई है। आये दिन जाम की स्थिति बन रही है । बताते है कि, सब्जी एवं फल विक्रेताओं को अन्य स्थान पर भेजे जाने का विवाद इतना बढ़ गया था कि उपसरपंच परिहार पर जानलेवा हमला तक हो गया था और 307 सहित कई गम्भीर धाराओं में मामला तक दर्ज हो चुका है। बढ़ती ट्रैफिक समस्या और फल,सब्जी विक्रेताओं के एक बार फिर इसी क्षेत्र में आने से बढ़ रही परेशानीयो को लेकर ग्राम पंचायत उपसरपंच ब्रजभूषण सिंह परिहार से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, ग्राम पंचायत की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विवाद की स्थिति होने से दो बार फिर से चौकी बामनिया में आवेदन देकर लोगो को हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने को कहा गया लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नही की जा रही है।

24 घंटे में 43.03 मिलीमीटर वर्षा दर्ज

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले में बीते 24 घंटे में 25 जुन प्रातः 08 बजे तक 43.03 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। झाबुआ में 89.20 मि.मी, रामा में 49.20 मि.मी, राणापुर में 22.20 मि.मी, मेघनगर में 34.00 मि.मी, थान्दला में 60.40 मि.मी, पेटलावद में 3.20 मि.मी। कुल 258.20 मि.मी वर्षा हुई। जिले में 1 जून से 25 जून 2025 प्रातः 8 बजे तक 221.25 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के झाबुआ में 339.20 मि.मी, रामा में 213.40 मि.मी, राणापुर में 252.90 मि.मी, मेघनगर में 227.20 मि.मी, थान्दला में 205.60 मि.मी, पेटलावद में 89.20 मि.मी कुल 1327.50 मि.मी दर्ज की गई। गत वर्ष इसी अवधि में औसत वर्षा 92.33 मिलीमीटर थी।

खेत-खेत में यूरिया देश-विदेश में भूरिया

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले राष्ट्रीय नेता स्व. दिलीप सिंह भूरिया की दसवीं पूर्णतिथि पर माही की गूंज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। निश्चित रूप से झाबुआ के ठेठ ग्रामीण क्षेत्र माछलिया से निकलकर जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले कर्मठ नेता स्व. दिलीप सिंह भूरिया सच्चे जननेता थे। उनके निधन के 10 वर्षों बाद भी वे आम लोगों की आस्था से जुड़े हैं। आज भी उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कई जनसभाएं की। वे अक्सर अपने संबोधन में कटाक्ष करते हुए कहते थे कि, नाचे कुदे वांदरी और खीर खाई फकीर।

समोसे में आलू और बिहार में लालू की तर्ज पर ही जिले में नया नारा चला था कि, खेत-खेत में यूरिया और झाबुआ जिले में भूरिया। स्वं. दिलीप सिंह भूरिया 6 बार जिले से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उनका जन्म 18 जून 1944 को हुआ था वे 1998 - 2001 तथा 2002 से 2004 तक अनुसूचित जनजाति आयोग कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त के चेयर मेन रहे। उन्होंने गरीब आदिवासियों और भूमि मजदूरों के उत्थान, दहेज और अंध श्रद्धा को बढ़ावा देने जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। आदिवासी सेवा संघ झाबुआ आदिवासी विकास परिषद मध्य प्रदेश के माध्यम से आंदोलन, आदिवासी पहचान और नेतृत्व की स्थापना के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली के सक्रिय सदस्य रहे।

हमेशा ग्राम सभा को सशक्त और मजबूत बनाने की पैरवी करने वाले भूरिया कहते थे कि, ना लोकसभा और ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। आदिवासी समाज की शान दिलीप सिंह भूरिया समाज की अमूल्य धरोहर है और समाज की आवाज को दिल्ली की संसद में पूरी बेबाकी के साथ अठाते थे। उन्हें कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में समान आदर मिलता था।

रोजगार मेला 2 जुलाई को

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भोपाल तथा रोजगार संचालनालय मध्यप्रदेश के निर्देश पर 2 जुलाई को शासकीय आईटीआई झाबुआ में प्रातः 11 बजे रोजगार/स्व-रोजगार योजनान्तर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में निजी क्षेत्र की कम्पनियों/प्रतिष्ठानों में उपलब्ध लगभग 200-300 रिक्त पदों के लिये चयन किया जायेगा। जिले के शिक्षित बेरोजगार महिला/पुरुष अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18-35 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता-5वीं से 12वीं, आईटीआई, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा एवं स्नातक उत्तीर्ण हैं वे साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकते हैं।

स्वच्छ पेयजल को तरस रहा है जिला, प्रशासन का अपनी ढपली अपना राग

सरकार की हर घर नल जल योजना गर्त में

माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे तो सरकार के दावे बहुत कुछ कहते है। मगर स्थिति धरातल की जगह गर्त में जा पहुंचती है। सरकार ऐसी ही एक योजना हर घर नल-हर घर जल का भी जिले में जनाजा निकला पड़ा है। मतलब यह योजनाएं जिले में लागू तो हो गई लेकिन धरातल पर न उतरते हुए गर्त में चली गई। वैसे तो जिले में कई योजनाएं इस तरह से गर्त में जा चुकी है। लेकिन सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना हर घर जल-हर घर नल भी जिले में अब तक लोगों तक नही पहुंच पाई है। यानि आजादी के सात दशक बाद भी जिले के कई घरों व ग्रामों में अब तक नल -जल योजना नही पहुंच पाई है। जहां पहुंची वहां सिर्फ टंकियां और पाइप लाइन ही पहुंची जल तो पहुंच ही नहीं पाया। जिले के जिन ग्रामों में यह योजना येन-केन प्रकारेण पहुंच भी गई तो स्थिति इतनी खराब है कि, वहां स्वच्छ जल की कल्पना साकार होती दिखाई नही दे रही है। मगर इसके उलट सरकार और उसके तंत्र के दावे है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे है। जिले की जनता शिकायतें लेकर प्रशासन के पास पहुंचती तो है लेकिन प्रशासनिक तंत्र के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर शिकायत जिले के बाहर पहुंच जाती तो फिर तंत्र में बैठे भ्रष्ट उसका निराकरण, शिकायत कर्ता पर दवाब बनाकर शिकायत वापस लेने के रूप में करते है। यह कोई नई कहानी नही है। ऐसे कई मामले है जिनमें जिले में बैठे भ्रष्ट अधिकारी शिकायतकर्ता को या तो डरा-धमका कर, या लेन-देन कर सेटल करते और शिकायतों का निराकरण करवाते है। फिलहाल स्वच्छ पेयजल का मुद्दा जिले में गर्माया हुआ है। जिले के अधिकतर ग्रामों में स्वच्छ जल अब तक भी नहीं पहुंच पाया है। ग्रीष्म ऋतु में तो कई जगह हालात ऐसे हो जाते है कि, लोग सूखी नदियों व नालों में झीरी खोदकर अस्वच्छ पानी पीने को मजबूर हो जाते है। अखबारों में खबरें प्रकाशित होने के बाद प्रशासन अपनी ढपली लेकर निकलता और अपना राग गाकर मामले को शांत कर देता है। बाकी आमजन की स्थिति वही ढाक के तीन पात।

ताजा मामला थांदला तहसील के ग्राम भामल में सामने आया जब यहां भारी मात्रा में लोग उल्टी दस्त का शिकार हो गए। ग्रामीण लोगों का कहना था कि, पेयजल में खराबी होने के कारण यह मामला हुआ। मगर यहां भी प्रशासन ने अपनी ढपली अपना राग गाते हुए या तो ग्रामीणों की आवाज को दबा दिया या मामले को दूसरी तरफ मोड़ने का षड़यंत्र रच दिया। जांच अपने हिसाब से की, रिपोर्ट भी अपने हिसाब की और आ गई। और प्रशासन इस बात से नकर गया कि, पानी में किसी तरह की कोई खराबी है। मगर भामल के ग्रामीण है कि, अब भी अपनी बात पर डटे हुए है। क्योंकि अगर पानी में खराबी ना होती तो फिर गांव में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होना संभव नहीं थी। मगर भामल में अब तक भी लगातार उल्टी - दस्त के मरीज बढ़ते ही जा रहे है। हालांकि प्रशासन ने मरीजों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जरूर की है, लेकिन असल कारणों का पता लगाने से अब भी प्रशासन कोषो दूर ही नजर आ रहा है।

यह तो महज एक ग्राम भामल की कहानी है, लेकिन पूरे जिले में स्थिति को देखा जाए तो कुछ खास फर्क दिखाई नहीं देता। जो प्रशासन व सरकार के स्वच्छ जल के वादों और दावों को खोखला साबित कर रहा है। कई ग्रामों में तो पेयजल की सप्लाय 15-15 दिनों में हो रही है। तो कहीं ग्रामीण हेंडपंप और कुंओं पर अब भी आश्रित है। जिले में बारिश की शुरूआत हो चुकी है और अच्छी बरसात का दौर चल रहा है। इस बीच पेयजल स्त्रोतो में स्वच्छ जल उपलब्ध होना दिवा स्वप्न साबित हो रहा है। कुंओं में बारिश का पानी बहकर मिल रहा है जिसकी शुद्धता पर 100 प्रतिशत प्रश्न चिन्ह है। नदी, नालों का पानी भी अब मटमेला ही दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में जिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्राकृतिक जल स्त्रोतों का उपयोग करते है, वह 100 प्रतिशत खतरे के निशान पर है। यह नहीं कहा जा सकता कि, भामल जैसी घटना कहीं ओर नही होगी।

जिले के कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे है जहां पेयजल आपुर्ति के लिए जन आंदोलन चल रहे है, लेकिन प्रशासन है कि, कुम्भकर्णीय नींद में सोया हुआ है। सुनवाई तो ठीक प्रशासन ने अब तक उनकी तरफ झांक कर भी देखा तक नहीं है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी आमजन के इस आंदोलन के साथ है। मगर इसके अलावा तहसील या जिले में बैठे जनप्रतिनिधियों ने इस तरह के आंदोलन से सिर्फ कन्नी ही काटी है।

जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पूरे शहर में नल-जल योजना के तहत एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जाता है। मगर इसकी गुणवत्ता का भगवान ही मालिक है। वर्षा ऋतु को छोड़ भी दे तो यहां सालभर मटमेला, गंधला और दुर्गंध वाला पानी ही आमजन को नसीब होता है। जबकि शहर वासियों को स्वच्छ जल देने के लिए सरकार ने करोड़ों खर्च कर नई योजना बनाई, उसमें अनास नदी पर बड़ा बैराज बनाया। शहर में नई पाइप लाइन डाली गई। मगर अफसोस की यह पाइप लाइन पिछले कई वर्षों में भी पूरे शहर में नहीं बिछ पाई। जहां पाइप लाइन नहीं बिछी है वहां आज भी लोग जलआपुर्ति को लेकर जद्दोजहद करते देखे जा सकते है। शहर के जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछ चुकी है वहां भी गंदा और बदबूदार पानी ही लोगों को मिल रहा है। उस पर सितम यह कि, नगरपालिका पेयजल के नाम पर हर कनेक्शन पर 200 रुपये वसूल रही है। वैसे देखा जाए तो यह पेयजल शुल्क सिर्फ 15 दिनों का ही बनता है, क्योंकि नल तो सिर्फ 15 दिन ही आते है। बावजूद इसके पेयजल के नाम पर नगरपालिका और प्रशासन गंदा पानी ही जनता को पीने के लिए दे रहे है। अब वर्षा काल शुरू हो चुका है और अनास नदी का पानी मटमेला बह रहा है। इसी नदी का पानी नगरपालिका, शहर में फिल्टर कर सप्लाय करती है। लेकिन वर्तमान में फिल्टर प्लांट से भी नदी जैसा मटमेला पानी ही सप्लाय हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार नल से सप्लाय हो रहा पानी पीने योग्य बिल्कुल भी नही है।

वही जिले के एक बडे कस्बे खवासा की बात करे तो यहा आजादी के 70 साल बाद भी स्थाई पेय जल व्यवस्था के लिए आंदोलन किए जा रहै है। तथा यहा पर 80 रूपये राशि मासिक पेयजल वितरण की पंचायत द्वारा वसुली जाती है पर पेय जल सप्लाई 86 वाल्व से 15 दिन में एक बार होता है।

मगर जिले में बन रही पेयजल को लेकर इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन के पास कोई पुख्ता इंतेजाम या योजना नजर नहीं आ रही है। शिकायतें होती है, मगर शिकायतकर्ताओं की आवाज को दबाकर प्रशासन अपनी ढपली अपना राग अलापते हुए पानी को स्वच्छ बता देता है और स्थिति ढाक के तीन पात ही नजर आती है। कुल मिलाकर सरकार की योजना और प्रशासनिक तंत्र के दावों की हवा इस मुद्दे पर निकलती नजर आती है। जो आजादी के 7 दशक बाद भी जिले को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हुई है।

खबर के बाद निरस्त हुआ प्राचार्यों के स्थानांतरण का आदेश, अब सरपंच उतरे मैदान में

माही की गूंज, पेटलावद।

गूंज के पिछले अंक में बरवेट संकुल मोतीलाल मालवीय सहित जिले के तीन प्राचार्यो के विभाग द्वारा जारी किए गए स्थानन्तरण आदेश के नियम विरुद्ध और राजनीतिक द्वेष के चलते हुए आदेश पर खबर प्रकाशित की थी। खबर के बाद प्रशासन में उक्त आदेश को लेकर हड़कम्प मच गया और ताबड़तोड़ में आदेश निरस्त कर दिए गए। 17 जून को कलेक्टर जन जातिय एवं आदिमजाति विभाग द्वारा जारी किए गए थे जिंसमे पेटलावद विकास खण्ड के बरवेट संकुल सहित जिले के अन्य दो स्कूलों के प्राचार्यो का स्थानन्तरण किया गया था। दोनों ही आदेशों को देखा जाए तो विभाग ने स्थानन्तरण आदेश ओर निरस्ती के आदेश एक ही तारिक मतलब 17 जून को ही निकाले। साफ है विभाग द्वारा किये गए आदेशों के बाद हुई फजीयत से बचने के लिए बेक डेट में ही निरस्ती आदेश निकाले गए।

क्षेत्र के सरपंचों ने दिया ज्ञापन

ताबड़तोड़ में निकले दो-दो आदेशों के बाद क्षेत्र बरवेट क्षेत्र की चार से पाँच ग्राम पंचायतों के सरपंचो ने बरवेट संकुल के प्राचार्य मोतीलाल मालवीय पर गम्भीर आरोप लगाते हुए बीईओ को ज्ञापन सोप कर प्राचार्य को हटाने की मांग की। अचानक से क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के इस प्रकार से सामने आकर प्राचार्य का विरोध करने के पीछे कौन राजनीति कर रहा है ये भी चर्चा का विषय है। प्राचार्य मालवीय से इस विषय मे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मेरे संकुल क्षेत्र सहित मेरी संस्था की जांच करने पर पता चल जाएगा कि आखिर दिक्कत क्या है। शासन के नियमानुसार चलना और संकुल को चलाना कुछ लोगो को रास नही आ रहा कुछ समय मे रिटायर्ड हो जाऊँगा पर इस प्रकार के आरोप कभी नही लगें जो साफ दर्शाता है कि हीन भावना से ग्रसित होकर झूठी शिकायत की जा रही है।

: कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला झाबुआ :

: आदेश :

प्राचार्यों के स्थानन्तरण आदेश को निरस्त करने के आदेश।

पुराने तहसील परिसर की शुरू ही हिस्सा पाती, अब समोसे-कचोरी की दुकान हुई शुरू

माही की गूंज, पेटलावद।

नये भवन के निर्माण होते ही पुराने भवन पर कैसे कब्जा किया जाए ? इसके लिए कई संगठन योजना बना रहे हैं की, जैसे ही भवन खाली हो इसको प्रसासनिक जोड़तोड़ बिठा कर अपने लिए सुरक्षित किया जाए। अभी नये तहसील भवन का उदघाटन भी नही हुआ था कि पुराने भवन की हिस्सा पाती शुरू हो गई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय की नई बिलि्ंडग में शुरू हो चुकी हैं और जिस भाग में अनुविभागीय राजस्व न्यायालय का कार्यकाल था उस भाग को मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से चल रहे संगठन नारी शक्ति संकुल संगठन पेटलावद को कैफे संचालित करने के लिए दिया गया है। उक्त कैफे का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और उदघाटन में मध्यप्रदेश की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया पहुँच कर किया। फिलहाल तहसील कार्यालय इसी पुराने भवन में होने से चहल पहल है और नए भवन में तहसील कार्यालय जाते ही यहां की रौनक खत्म हो जाएगी ऐसे में आजीविका का ये दीदी कैफे कितना सफल होकर चलता है ये देखना दिलचस्प होगा। इस कैफे की शुरूआत के लिए प्रशासन ने क्या शर्ते रखी है या किस आधार पर शासकीय भवन संगठन को दिया गया है इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित अत्याधुनिक बालक छात्रावास का उद्घाटन बहुत जल्द होगा

छात्रों को मिलेगी कई सुविधाएं

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

सारंगी के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला 3 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक बालक छात्रावास अब बनकर तैयार हो गया है। यह विशालकाय परियोजना, जो क्षेत्र में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, अब उद्घाटन की तैयारी में है। यह नया छात्रावास छात्रों को आधुनिक और आरामदायक आवास प्रदान करेगा, जिसमें अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सुविधाओं में हवादार कमरे, स्वच्छ शौचालय, विशाल अध्ययन कक्ष, मनोरंजन क्षेत्र और खेल सुविधाएं शामिल होने की उम्मीद है।

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि, इस छात्रावास के निर्माण से सारंगी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी। यह छात्रावास उन छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, जिन्हें दूरदराज के क्षेत्रों से आकर पढ़ाई करनी होती है।

उद्घाटन समारोह की तैयारिया चल रही हैं, और उम्मीद है कि, जल्द ही किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। इस परियोजना को सारंगी के शैक्षिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जा रहा है।

प्रभारी तहसीलदार का हुआ स्थानन्तरण, अनिल बघेल को मिली पेटलावद की जिम्मेदारी

माही की गूंज, पेटलावद।

स्थानन्तरण के दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम था। उस सूची में सबसे ऊपर पेटलावद के प्रभारी तहसीलदार हुकुमसिंह निगवाल का था, तहसीलदारो की पहली सूची में तहसीलदार निगवाल का नाम नही था। जिंसमे तहसीलदारो के स्थानन्तरण जिले से बाहर किये गए थे। लेकिन 24 जून को कलेक्टर कार्यालय से जारी स्थानन्तरण सूची में प्राभारी तहसीलदार निगवाल का नाम दर्ज है और उन्हें राणापुर का तहसील का प्रभारी बनाया गया हैं वही पेटलावद में अनिल बघेल जो कि थांदला में प्रभारी तहसीलदार के पद पर थे अब पेटलावद तहसील सम्भालेंगे । जिले के ज्यादातर तहसीलदार और नायाब तहसीलदारो को इधर उधर किया गया है। सारंगी टप्पा तहसील के नायाब तहसीलदार विजेन्द्र कटारे को झकनावदा, पेटलावद तहसील की नायाब तहसीलदार की अंकिता भिड़े को सारंगी टप्पा तहसील भेजा गया है।

अवैध शराब के साथ कार जप्त

माही की गूंज, सारंगी।

पेटलावद व सारंगी पुलिस ने रात्रि में मुखबिर की सुचना पर घेरा बंदी कर शराब से भरी कार क्रमांक एमएच 06 एस 6120 को पकडी गई। उक्त वाहन बदनावर-भैसोला से अवैध शराब भर कर आ रहा था। पुलिस ने वाहन में भरी 38 अवैध शराब की पेटीया जप्त कर कार को भी जप्त कर आशुवेन्द्र उर्फ धीरू पिता उदयभानसिंह तोमर (30), निवासी ग्राम बरमुपुर, थाना औरैया (उ.प्र.) हाल निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी झाबुआ के विरूद्ध मामला दर्ज किया। जप्त अवैध शराब की कुल कीमत 5 लाख 20 हजार 6 सौ बताई जा रही है।

कलेक्टर ने कर दी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की उठा पटक

13 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के हुए तबादले

माही की गूंज, झाबुआ।

कार्यालय कलेक्टर जिला झाबुआ (म.प्र.)

क्रमांक/स्थापना/1/324890/2025 झाबुआ, दिनांक24-06-2025

आदेश

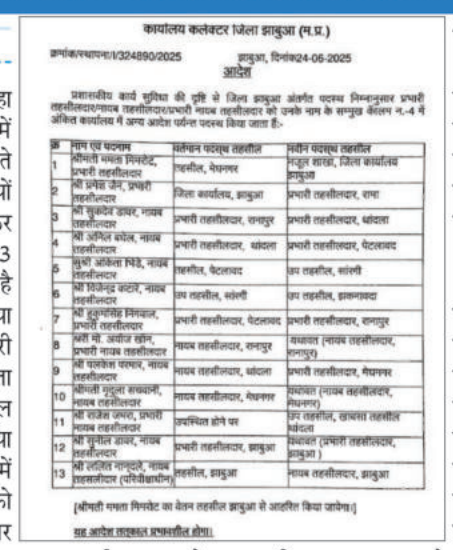

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से जिला झाबुआ अंतर्गत पदस्थ निम्नानुसार प्रभारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार/प्रभारी नायब तहसीलदार को उनके नाम के सम्मुख कॉलम न.-4 में अंकित कार्यालय में अन्य आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है:-

क्र	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थ तहसील	नवीन पदस्थ तहसील
1	श्रीमती ममता मिमरोट, प्रभारी तहसीलदार	तहसील, मेघनगर	नजूल शाखा, जिला कार्यालय झाबुआ
2	श्री प्रमेश जैन, प्रभारी तहसीलदार	जिला कार्यालय, झाबुआ	प्रभारी तहसीलदार, रामा
3	श्री सुकदेव डावर, नायब तहसीलदार	प्रभारी तहसीलदार, राणापुर	प्रभारी तहसीलदार, थांदला
4	श्री अनिल बघेल, नायब तहसीलदार	प्रभारी तहसीलदार, थांदला	प्रभारी तहसीलदार, पेटलावद
5	सुश्री अंकिता भिड़े, नायब तहसीलदार	तहसील, पेटलावद	उप तहसील, सारंगी
6	श्री विजेन्द्र कटारे, नायब तहसीलदार	उप तहसील, सारंगी	उप तहसील, झकनावदा
7	श्री हुकुमसिंह निंगवाल, प्रभारी तहसीलदार	प्रभारी तहसीलदार, पेटलावद	प्रभारी तहसीलदार, राणापुर
8	श्री मो. अजीज खान, प्रभारी नायब तहसीलदार	नायब तहसीलदार, राणापुर	यथावत (नायब तहसीलदार, राणापुर)
9	श्री पलकेश परमार, नायब तहसीलदार	नायब तहसीलदार, थांदला	प्रभारी तहसीलदार, मेघनगर
10	श्रीमती मृदुला सचवानी, नायब तहसीलदार	नायब तहसीलदार, मेघनगर	यथावत (नायब तहसीलदार, मेघनगर)
11	श्री राजेश जमरा, प्रभारी नायब तहसीलदार	उपस्थित होने पर	उप तहसील, खवासा तहसील थांदला
12	श्री सुनील डावर, नायब तहसीलदार	प्रभारी तहसीलदार, झाबुआ	यथावत (प्रभारी तहसीलदार, झाबुआ)
13	श्री ललित नागदरे, नायब तहसीलदार (परिवीक्षाधीन)	तहसील, झाबुआ	नायब तहसीलदार, झाबुआ

[श्रीमती ममता मिमरोट का वेतन तहसील झाबुआ से आहरित किया जावेगा।]

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा ने राजस्व अमले में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए कई राजस्व अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया है। पूरे जिले में 13 राजस्व अधिकारी ऐसे है जिन्हे इधर से उधर किया गया है। इनमें मेघनगर प्रभारी तहसीलदार श्रीमती ममता मिमरोट को हटाकर नजूल शाखा झाबुआ में पदस्थ किया गया है। जिला कार्यालय में पदस्थ प्रभारी प्रमेश जैन को रामा प्रभारी तहसीलदार बनाया गया है। साथ ही राणापुर नायब तहसीलदार सुकदेव डावर को थांदला प्रभारी तहसीलदार, थांदला प्रभारी तहसीलदार अनिल बघेल को पेटलावद प्रभारी तहसीलदार, पेटलावद प्रभारी तहसीलदार हुकमंसिह निंगवाल को राणापुर प्रभारी तहसीलदार पदस्थ किया गया है। इसी सूची में खवासा (थांदला) के नायब तहसीलदार पलकेष परमार को मेघनगर का प्रभारी तहसीलदार बनाया गया है। इसके अलावा नायब तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन किया गया है।

इतने बड़े हेर-फेर के बावजूद झाबुआ प्रभारी तहसीलदार यथावत झाबुआ तहसीलदार बने रहेंगे। हालांकि बताया यह जा रहा है कि, प्रभारी तहसीलदार झाबुआ सुनील डावर का स्थानांतरण रामा कर दिया गया था और झाबुआ तहसीलदार का प्रभार प्रमेश जैन को दे दिया गया था। लेकिन आदेश में संशोधन हुआ और झाबुआ तहसीदार को फिर से यथावत कर दिया गया। स्थानांतरण सूची में अचानक हुए इस बदलाव के बाद सरकारी गलियारों में चर्चाओं का दौर गर्मा गया है।

सत्तामोह में संविधान और लोकतंत्र पर कांग्रेस के आपातकाल का खतरा ना भूलें युवा

माही की गूंज,झाबुआ।

जीवन में इतिहास की अच्छाई व बुराई को अवश्य ही जानना चाहिए, ताकि वर्तमान को सुनियोजित किया जा सके और भविष्य में ऐसी कोई घटना न घट पाए जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे इतिहास की दुहाई दे। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति जिसे कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के बारे में पता होता है या वह इसका अध्ययन करता है तो उसे कांग्रेस शासन के आपातकाल पर क्रोध आयेगा, वह भ्रत्सर्ना करेगा, कांग्रेस के नियम या देश को चलाने वाली पद्धति से उसका विश्वास उठेगा।

भारत के साथ विश्व के सभी युवाओं को भारत देश में लगे आपातकाल को समझना चाहिए। सन् 1975 जून 25 की रात्रि 11-45 बजे तत्कालिन प्रधानमंत्री कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा वाले आध्यादेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अलि अहमद के हस्ताक्षर करवा लिए और सुबह 6 बजे केबिनेट की आपात बैठक बुलाकर उस पर मुहर लगा ली। जिसके बाद रेडियो पर घोषणा कर दी कि, भाईयों-बहनों देश के राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने की जरुरत नहीं है। इसके साथ देश में आपातकाल शुरु हो गया। इंदिरा गांधी के कहे अनुसार जनता आतंकित नहीं हुई किंतु सरकार का आंतक शुरु हो गया। सभी विपक्षी, विरोधी नेता, समाजसेवी, पत्रकार, संपादको को जेल में बंद कर दिया गया। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी तो 25 जून की मध्य रात्री से ही शुरु हो गई थी।

युवाओं के साथ देश के प्रत्येक वर्ग को यह जानना आवश्यक है कि, तत्कालिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया..? उसके पीछे कांग्रेस की मंशा क्या थी...? और किस योजनाबद्ध तरिके से आपातकाल को लगाया गया...?

वर्तमान में कांग्रेस के राहुल गांधी जो हर सभा और प्रत्येक कार्यक्रम में संविधान की कॉपी लिए हाथ उठाकर जनता को बताते है कि, भाजपा सरकार के साए में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। अब इसी बात को लेकर विश्वभर के युवा इतिहास के पन्ने पलटकर सन् 1975 में पहुंचे और कुछ जानकारी का अध्ययन करे तो कांग्रेस के षडयंत्र के स्वरुप को पहचान सकेगे। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी निर्वाचित हुई। 1971 में राईबरेली चुनाव में गड़बड़ी को लेकर समाजवादी नेता राजनारायण ने शिकायत कर याचिका दायर की। 1975 जून 12, को इलाहबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी माना और इस्तिफा देने की बात कही। इंदिरा गांधी ने सुप्रिम कोर्ट में अपील की, 24 जून को एससी ने शर्तो के साथ राहत दी, कितु संसद में मतदान के अधिकार छिन लिए, 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकती इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अटल रही।

पदमोह, सत्तामोह में अंधी कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र भारत में राजनीति अपराध किया और देश को आपातकाल देकर कालकोठरी सा बना दिया। इंदिरा गांधी के इस अपराध का दंड पूरे भारत को मिला, और लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक कलंक बन गया। यदि इंदिरा गांधी 1977 चुनाव में दोबारा विजय होती तो भारत के लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे पर जो प्रभाव पड़ता उससे राष्ट्र पर खतरा हमेशा बना रहता। क्योंकि उसके पूर्व आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन, संविधान की मूल आत्मा को बदलने का एक प्रयासभर था, जिसमें एक दलीय प्रणाली को स्थापित करने की मंशा थी। यह एक तरह से संविधान को बदलने का प्रयास था। कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड ने संपादकीय में लिखा था कि, देश अब एक दलीय लोकतंत्र की दिशा में आगे बढें। बीके नेहरु जो की इंदिरा के करीबी सहयोगी थे वो एक पत्र में लिखते है कि, संसदीय लोकतंत्र हमारी जरुरतों का उत्तर देने में सक्षम नहीं। इसलिए इंदिरा गांधी से आग्रह किया कि, जब आपके पास दो-तीहाई बहुमत है तो संविधान में मौलिक परिवर्तन कर दिजिए।

यदि 1977 में देश फिर से कांग्रेस सरकार के हाथ में चला जाता तो निशंदेह संविधान जो की खतरे पड़ तहस-नहस हो जाता। फिर भी कांग्रेस सरकार ने आपतकाल में एक साथ 53 अनुच्छेद संविधान के संशोधित किए। वहीं आपातकाल के पूरे 21 महिनों में 48 आध्यादेश पारित किए गए। आपातकाल के समय कांग्रेसियों ने असहमत विरोधी दलों पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लाखों नेताओ को जेल में डाला, और अनेक गैर-राजनैतिक, सामाजिक संगठनों की आवाज दबाई। इसके पिछे कांग्रेस का उद्देश्य था बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करके देश में एकदलीय प्रणाली को शक्तिशाली बनाना। इस अलोकतांत्रिक विचार के साथ कांग्रेस, देश में एकमात्र राजनीतिक शक्ति बनकर उभरना चाहती थी।

हालांकि 1975 जून 25 को भारत देश में लगने वाला यह आपातकाल तीसरा आपातकाल था जो कि भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बना, इसके पहले सन् 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय दूसरा आपातकाल लगाया गया था तब भी कांग्रेस की सरकार थी और पहला आपातकाल सन् 1968 में लगाया था जब भारत-चीन का युद्ध हुआ था तब सरकार कांग्रेस की थी। देश में आपातकाल कब और क्यों लगाना चाहिए इस पर सभी वर्गो को विचार करना चाहिए। जब देश में बाहरी युद्ध, बाहरी संक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो या फिर राज्य सरकारें संविधान के अनुरुप कार्य करने में विफल हो तब आपातकाल लगाना चाहिए। परंतु सत्तामोह में कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी और देश को आपातकाल का काला कंलक दे दिया।

रिंकेश बैरागी

बहरहाल, भारत देश में प्रत्येक विद्यार्थी को आपातकाल का दंश पता होना चाहिए, इसके लिए सरकार को आपातकाल का इतिहास पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना आवश्यक होगा। आपातकाल के तीन दशक बाद कांग्रेस की सरकार में ही आपातकाल को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। किंतु कोविड-19 में पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए भाजपा सरकार ने ही कुछ हिस्सो को कम किया। भाजपा सरकार को तो आपातकाल के इस अध्याय को विद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलीत करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी कांग्रेस का अलौकतांत्रिक और असंवैधानिक काली करतूत को समझे भी और जाने भी।

संपादकीय

बेटियां संवेदनशील

देशकाल-परिस्थितियों और बदलती जरूरतों के अनुरूप वैश्विक स्तर पर एक सूक्ष्म, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव दृष्टिगोचर हो रहा है। यह बदलाव लिंग प्राथमिकताओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण में आ रहे परिवर्तन का है। जैसा कि हाल ही में 'द इकनॉमिस्ट' द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कों के प्रति सदियों पुराना झुकाव अब कम हो रहा है। दुनियाभर में, अतिरिक्त पुरुष जन्म की संख्या- जो वर्ष 2000 में 1.7 मिलियन तक अधिक थी, साल 2025 तक लगभग दो लाख तक गिर गई है। निस्संदेह, यह प्रजनन विकल्पों में एक अप्रत्याशित बदलावों का संकेत है। यहां तक कि दक्षिण कोरिया और चीन में, लिंग अनुपात सामान्य या यहां तक कि बेटी की पसंद के संकेत दिखाने लगा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस बदलाव की असल वजह क्या है... दरअसल, माता-पिता में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि बेटियां उनकी ढलती उम्र में धीरे-धीरे अधिक विश्वसनीय देखभाल करने वाली साबित हो सकती हैं। उन्हें परिवार से गहरे तक जुड़े रहने की अधिक संभावना के रूप में देखा जाने लगा है। आज बेटियों को बेटों के मुकाबले बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शनकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। तेजी से कामकाजी दुनिया का हिस्सा बनने के कारण वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती जा रही है। बल्कि कई देशों में तो महिलाओं की बैचलर डिग्री की संख्या तक पुरुषों की तुलना में अधिक है। पश्चिमी देशों में गोद लेने और आईवीएफ के डेटा दिखाते हैं कि बेटियों को चुनने की दिशा में स्पष्ट झुकाव है। दरअसल, पश्चिमी देशों के एकल परिवारों में बेटे अपनी गृहस्थी बसाकर मां-बाप को उनके भाग्य पर छोड़ जाते हैं। ऐसा माना जाने लगा है कि बेटियां बेटों के मुकाबले में ज्यादा संवेदनशील होती हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव में मां-बाप को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती हैं। जिसके चलते लोग बेटों के मुकाबले बेटियों को अपनी प्राथमिकता बनाने को तरजीह देने लगे हैं।

वहीं भारत में परिस्थितियां एक जटिल तसवीर प्रस्तुत करती हैं। यूं तो सदियों से भारत का समाज पुत्र मोह की ग्रंथि से ग्रस्त रहा है। हालांकि, अब आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि देश में शिशु लिंग अनुपात दर में सुधार हुआ है। लेकिन लिंग चयन के लिये किए जाने वाले गर्भपात पर शासन व प्रशासन की कानूनी सख्ती और जागरूकता अभियानों के बावजूद परंपरागत रूप से समाज में गहरी जड़ें जमाने वाला बेटा मोह अब भी प्राथमिकता बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5(2019-21) का सर्वे चिंता बढ़ाने वाला है। सर्वे के अनुसार, लगभग 15 फीसदी भारतीय माता-पिता अभी भी बेटियों की तुलना में बेटों की आकांक्षा रखते हैं। यही वजह है कि हरियाणा,पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विषम शिशु लिंगानुपात चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा, भारत में बेटी वरीयता, जहां यह मौजूद है, अक्सर सशर्त होती है। लड़कियों को भावनात्मक लगाव या घरेलू स्थिरता के लिये तो महत्व दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पोषण, शिक्षा या विरासत तक उन्हें समान पहुंच दी जाए। भारतीय समाज में दहेज जैसी सांस्कृतिक प्रथाएं आज भी बेटी के माता-पिता की बड़ी चिंता बनी रहती हैं। परंपरावादी समाज में यह धारणा बलवती रही है कि बेटियां दूसरे परिवार की हैं। यही वजह है कि ग्रामीण और शहरी गरीब समुदायों में लड़कियां हाशिये पर रख जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत को लिंग समानता के वैश्विक आंदोलन की किसी भी तरह अनदेखी नहीं करनी चाहिए। साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के नीतिगत हस्तक्षेप को जन्म सांख्यिकी से परे जाना चाहिए। नीति-नियंताओं को बालिका शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही समान संपत्ति अधिकार लागू करने, दहेज प्रथा की कुरीति को समाप्त करने की दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए। तभी भारतीय समाज में लिंगभेद की मानसिकता खत्म होगी और लैंगिक समानता की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही देश में तेजी से बढ़ती बुजुर्गों की आबादी के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

ट्रंप के दावों के बावजूद रूकेगा नहीं ईरान

आप ईरान के ठिकानों पर कोऑर्डिनेटेड बमबारी करें, फिर घोषणा कर दें, कि इस्राइल-ईरान युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। यह अमेरिकी दादागिरी का दीगर रूप है। खुद की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 'ट्रुथ सोशल' पर डोनाल्ड ट्रम्प बोले, 'यदि ईरान के पास परमाणु हथियार है, तो आप शांति नहीं पा सकते।' ऐसे बोल-वचन इसलिए, ताकि पश्चिमी देश खुश हो जाएं। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई अपरिहार्य और नैतिक रूप से उचित साबित हो। ये वही ट्रम्प हैं, जो बात-बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में दावत देते हैं। लेकिन, तोताचश्म पाकिस्तान ने बयान दिया, कि हम ईरान के साथ खड़े हैं।

अगर, परमाणु क्षमता का आकांक्षी ईरान शांति का दुश्मन है, तो अमेरिका के पास लगभग 5,244 परमाणु हथियार हैं, जो कि इस्राइल के अघोषित शस्त्रागार में अनुमानित संख्या से दस गुना अधिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अधिकरण (आईएइए) खुफिया के अनुसार, 'ईरान ने अभी तक परमाणु हथियार नहीं बनाया है।' ईरान परमाणु हथियारों के अप्रसार (एनपीटी) पर संधि का हस्ताक्षरकर्ता बना हुआ है। इजरायल नहीं है।

अमेरिका के पास 100 से अधिक देशों में 800 से अधिक सैन्य अड्डे हैं। इसकी तुलना चीन से करें, जो पड़ोसी क्षेत्रों में केवल एक विदेशी सैन्य अड्डे रखता है, या रूस, जो लगभग बीस सैन्य अड्डों का प्रबंधन करता है। यह वैश्विक स्थिरता का संकेत नहीं है। यह एक साम्राज्यवादी ढब है। पूरी दुनिया का चौधरी बने रहने की लिप्सा। विदेश संबंध परिषद के अनुसार, 'इस समय मध्य पूर्व में कम से कम 19 अमेरिकी मिलिटरी बेस हैं। इनमें से आठ स्थायी सैन्य ठिकाने हैं।' बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में बनाए अमेरिकी सैन्य ठिकाने हटवाने की हिम्मत वहां की कठपुतली सरकारें नहीं करतीं। अमेरिका ने पूरे मिडल ईस्ट में लगभग 40,000 सैनिक तैनात किये हैं।

क़तर में 1996 में निर्मित अल उदीद एयरबेस मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। यह ईरान द्वारा लक्षित स्थलों में से एक था। इस बेस पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का क्षेत्रीय मुख्यालय है, जहां 11,000 से अधिक अमेरिकी और गठबंधन सेना के सदस्य रहते हैं। यहां जो कुछ ईरानी हमला हुआ, ट्रम्प ने उसका मखौल उड़ाया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े की तैनाती है, जिसमें लगभग 9,000 सैन्य कर्मी और नागरिक कर्मचारी शामिल हैं। इराक में लगभग 2,500 अमेरिकी सैनिक हैं। 3 जनवरी, 2020 को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के प्रतिशोध में अल-असद और एरबिल अमेरिकी बेस को ईरान ने निशाना बनाया था।

वर्ष 2023 से ईरान समर्थित हौथी आतंकवादी समूह लाल सागर और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकी जहाजों पर हमले भी शामिल हैं। इराक में तेहरान समर्थित शिया

मिलिशिया, हिजबुल्लाह अलग से एक्टिव हैं। तो क्या ट्रम्प के 'सीज़ फ़ायर' बोल भर देने से बंदूकें गरजनी बंद हो जायेंगी? इस सच से अमेरिकन्स और इस्राइली वाकिफ हैं कि अकेला ईरान है, जिसके 'हमास', 'हिज़्बुल्लाह', 'इस्लामिक जिहाद' जैसे प्रॉक्सी मिलिटेंट्स, पूरे मिडल ईस्ट में पसरे हुए हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख 'स्विंग स्टेट' कूटनीतिक समाधान की कोशिश में हैं। सऊदी अरब, मिस्र, इराक, जॉर्डन सहित अधिकांश अरब राज्यों ने ईरान पर इस्राइल के हमलों की निंदा की है, ताकि तेहरान को इन पर भरोसा हो। ट्रम्प ने ऐसी प्रतिक्रिया सोची नहीं थी। युद्धविराम की तत्काल घोषणा की सबसे बड़ी वजह यह भी है।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रतिनिधि हुसैन शरीयतमादारी ने कट्टरपंथी कायहान अखबार से कहा, 'अब हमारी बारी है। हम बिना समय बर्बाद किए, अमेरिकी, ब्रिटिश, जर्मन और फ्रांसीसी जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद करेंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य के बरास्ते, वैश्विक तेल और गैस का पांचवां हिस्सा दुनियाभर को सप्लाई होता है, यह यदि बंद हुआ, तो विकल्प क्या है? सबसे व्यवहार्य विकल्प सऊदी अरब के बरास्ते ईस्ट-वेस्ट पेट्रो पाइपलाइन है, जो लाल सागर तक तेल पहुंचा सकती है। अन्य विकल्पों में इराक पाइपलाइन (आईपीएसए) और ओमान की खाड़ी में फुजैराह से जोड़ने वाली पाइपलाइनें शामिल हैं। यूरोपीय नेताओं की भृकुटियां इससे तन गई हैं। उन्हें लगता है, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को गद्दी से उतार देना अंतिम उपाय है।

दरअसल, अमेरिकी हमलों ने एक बार फिर से अयातुल्ला अली खामेनेई की जड़ों को मज़बूत कर दिया है। ईरान की नई पीढ़ी उनकी रूढ़िवादी और बुर्कापरस्त नीतियों का विरोध कर रही थी। जो युवा तेहरान की सड़कों पर सर्वोच्च नेता के खिलाफ मुट्ठी तानकर खड़े थे, वही चेहरे खामेनेई के समर्थन में खड़े हैं। बिना पब्लिक सपोर्ट के सत्ता परिवर्तन आसान नहीं है, इस सच को अमेरिकंस भी समझते हैं। यूरोपीय शक्तियां पहले ईरान के साथ यूरेनियम संवर्धन रोकने, अपने मिसाइल कार्यक्रम पर लगाम लगाने, और प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देना बंद करने के लिए एक समझौते पर दबाव डाल रही थीं। लेकिन ईरान ने पूर्ण रोक को अस्वीकार कर दिया है, कि उसका संवर्धन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

पुष्परंजन

यूरोपीय-अमेरिकन नेता भूल जाते हैं, कि पुतिन और शी पूरी ख़ामोशी से इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से सोमवार को मुलाकात की, और अमेरिकी हमले की भर्त्सना की। उत्तर कोरिया ने भी लगे हाथ ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है, और इसे संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन बताया। इसके मायने क्या निकलते हैं? उत्तर कोरिया, ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों का अहम सहकार है। ट्रम्प को पता है, मास्को-चीन-उत्तर कोरिया धुरी ईरान में एक्टिव हो चुकी है। मार्च, 2023 में पेइचिंग समझौते के बाद से, सऊदी-ईरान संबंधों ने नए अध्याय में प्रवेश किया है। उभयपक्षीय भरोसे की वजह से सऊदी अरब में फंसे 70 हज़ार से अधिक ईरानी हज यात्रियों को किंगडम ने आश्रय, चिकित्सीय देखभाल, और परिवहन प्रदान किया।

एक बात तो मानकर चलिए, मिडल-ईस्ट में कूटनीति निकट भविष्य के लिए मर चुकी है। अमेरिका-इस्राइल की कोशिश, सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी की कहानी दोहराने की होगी। ट्रंप ने 17 जून को सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिये अयातुल्ला अली खामेनेई का नाम लेते हुए लिखा, 'हमें ठीक से पता है कि तथाकथित 'सर्वोच्च नेता' कहां छिपा है। वह एक आसान लक्ष्य है, लेकिन वहां सुरक्षित है - हम उसे खत्म नहीं करने जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं।' आपने अफ़ग़ानिस्तान, इराक, लीबिया में नेता और सत्ता बदल तो दिया, लेकिन नव-स्थापित सरकारें अक्सर खुद को देश की समस्याओं को हल करने की चुनौती का सामना करने में असमर्थ पाती हैं। अफ़ग़ानिस्तान इसका ताज़ा उदाहरण है।

कड़वाहट से मुक्ति के लिये सम्मानजनक अलगाव

आज के बदलते सामाजिक परिवेश में, जहां रिश्ते जटिल होते जा रहे हैं, तलाक एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। भारत में तलाक की प्रक्रिया अक्सर लंबी, तनावपूर्ण और आरोप-प्रत्यारोप से भरी होती है। यह न केवल पति-पत्नी बल्कि उनके बच्चों और परिवारों के लिए भी भावनात्मक और आर्थिक बोझ बन जाती है। पारंपरिक तलाक कानूनों में, तलाक तभी दिया जाता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष पर 'गलती' (जैसे व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग) साबित करे। इसमें अक्सर एक लंबी और थकाऊ कानूनी लड़ाई शामिल होती है, जिसमें दोनों पक्षों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने पड़ते हैं, जिससे कड़वाहट और दुश्मनी बढ़ती है।

इसके विपरीत, 'नो-फॉल्ट' तलाक में, तलाक के लिए किसी भी पक्ष को दूसरे की गलती साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें बेवफाई, क्रूरता या परित्याग जैसे विशिष्ट कारणों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है और सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो दोनों पक्षों को सम्मानपूर्वक अलग होने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका मुख्य आधार 'अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका विवाह' होता है। ऐसे में, विकसित देशों के अनुभवों से सीखना महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां 'नो-फॉल्ट' तलाक एक सफल मॉडल साबित हुआ है।

विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में 'नो-फॉल्ट' तलाक ने कई सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। सबसे पहले, इसने तलाक की प्रक्रिया को काफी सरल और तेज बना दिया है। अदालती कार्यवाही कम होती है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। दूसरा, यह प्रक्रिया को कम विरोधी बनाता है। जब किसी एक पक्ष पर दोष नहीं लगाया जाता, तो कटुता और प्रतिशोध की भावना कम होती है, जिससे बच्चों के लिए बेहतर माहौल बनता है और भविष्य में सह-पालन की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, यह महिलाओं को सशक्त बनाता है। पारंपरिक तलाक कानूनों में अक्सर महिलाओं को अपनी स्थिति साबित करने के लिए अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता था, लेकिन 'नो-फॉल्ट' तलाक उन्हें इस बोझ से मुक्त करता है।

भारत में वर्तमान में तलाक के लिए विभिन्न आधार उपलब्ध हैं और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत आपसी सहमति से तलाक (धारा 13 बी) शामिल हैं। आपसी सहमति से तलाक 'नो-फॉल्ट' सिद्धांत के करीब है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें और प्रतीक्षा अवधि शामिल है। भारत में तलाक से संबंधित मौजूदा कानून, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, अभी भी काफी हद तक 'फॉल्ट-आधारित' है। जबकि आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है, यह तभी संभव है जब दोनों पक्ष सहमत हों और एक निश्चित अवधि तक अलग रह चुके हों। लेकिन अगर एक पक्ष तलाक नहीं चाहता, तो दूसरे पक्ष को क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग या मानसिक बीमारी जैसे आधारों पर दोष साबित करना पड़ता है। यह प्रक्रिया अक्सर अपमानजनक और लंबी खींचने वाली होती है, जिससे दोनों पक्षों को मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचता है।

शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) का मामला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस महत्वपूर्ण मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'अपरिवर्तनीय वैवाहिक विच्छेद' के आधार पर सीधे तलाक को मंजूरी दी। यह निर्णय इस मायने में उल्लेखनीय था कि यह ऐसे समय में आया जब तलाक के लिए कानून में 'अपरिवर्तनीय वैवाहिक विच्छेद' का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को 'नो-फॉल्ट' सिद्धांत की दिशा में एक बड़ा और प्रगतिशील कदम माना गया। इसका अर्थ यह है कि तलाक के लिए अब किसी भी पक्ष द्वारा विशेष दोष साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि केवल यह तथ्य कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तलाक के लिए पर्याप्त आधार होगा।

संयुक्त परिवार प्रणाली के कमजोर पड़ने के साथ, व्यक्ति अधिक आत्मनिर्भर हो रहे हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दे रहे हैं। महिलाएं अब आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र हैं और इसलिए वे ऐसे रिश्तों में बंधे रहने को तैयार नहीं हैं जो उन्हें खुश नहीं रखते। 'नो-फॉल्ट' तलाक इस तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। जब माता-पिता आरोप-प्रत्यारोप में उलझे रहते हैं तो इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। एक आसान और कम तनावपूर्ण तलाक प्रक्रिया बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करती है। साथ ही, अदालतों पर बढ़ते मुकदमों का बोझ भी इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि क्या तलाक प्रक्रियाओं को सरल और कम तनावपूर्ण बनाया जा सकता है।

डॉ. सुधीर कुमार

'नो-फॉल्ट' तलाक को पूरी तरह से अपनाने में कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले, संपत्ति का बंटवारा और गुजारा भत्ता निष्पक्ष होना चाहिए, विशेषकर कमजोर पक्ष के लिए। दूसरा, बच्चों का कल्याण और उनकी परवरिश सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता है ताकि कोई भी पक्ष वंचित न रहे। तीसरा, भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं का गहरा प्रभाव है, इसलिए इन संवेदनशीलताओं का ध्यान रखना ज़रूरी है। अंत में, यह सुनिश्चित करना होगा कि 'नो-फॉल्ट' तलाक का दुरुपयोग न हो।

आत्मनिर्भरता से रक्षा निर्यातक बनने के बीच चुनौती

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां रूस-यूक्रेन, इस्राइल-हमास और इस्राइल-ईरान जैसे युद्ध चल रहे हैं, वहीं भारत-पाकिस्तान के बीच 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भी सैन्य तैयारी की गंभीरता को रेखांकित किया है। ऐसे माहौल में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर विश्व का ध्यान केंद्रित हुआ है। भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। आयातक से निर्यातक देश बनने की ओर बढ़ता भारत अब वैश्विक मंच पर एक मजबूत और विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा है। 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियों ने देश के रक्षा निर्माण और निर्यात को गति दी है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2017-18 में मात्र 1,521 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 16,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। यह लगभग 950 प्रतिशत की वृद्धि है, जो यह दर्शाता है कि भारत अब रक्षा निर्माण और निर्यात के क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख रक्षा उत्पादों में आर्टिलरी गन सिस्टम्स (धनुष) आकाश मिसाइल प्रणाली, राडार सिस्टम्स (स्वाति राडार), गश्ती नौकाएं और मिसाइल बोट्स, डोर्नियर एयरक्राफ्ट, 'ध्रुव', बुलेटप्रूफ जैकेट्स, हेल्मेट्स, स्मॉल आर्म्स और गोला-बारूद, ड्रोन, यूएवी आदि शामिल हैं।

सरकार ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं मसलन रक्षा उत्पादन नीति, निजी कंपनियों को प्रोत्साहन, विदेशों में रक्षा अटेचेज़ की नियुक्ति, सिंगल विंडो क्लियरेंस, डिफेंस एक्सपो जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ-साथ टाटा, एल एंड टी, भारत फोर्ज जैसी निजी कंपनियों ने डिफेंस निर्यात को नया आयाम दिया है। सरकार ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे निजी कंपनियां भी रक्षा उत्पादन और निर्यात में भाग ले सकें। रक्षा निर्यात से जुड़े लाइसेंस और परमिशन अब सिंगल विंडो सिस्टम से मिल रहे हैं।

ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली भारत की रक्षा तकनीक की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। यह सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम 'ब्रह्मोस एयरोस्पेस' द्वारा विकसित की गई है। अब यह न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं का एक अभिन्न हिस्सा है, बल्कि भारत के डिफेंस निर्यात की पहचान भी बन रही है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने की दिशा में सफलतापूर्वक कदम बढ़ा चुका है। यह भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम 'ब्रह्मोस एयरोस्पेस' द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जो दुनिया

की सबसे तेज क्रूज़ मिसाइलों में से एक मानी जाती है। यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि इससे भारत विश्व के चुनींदा मिसाइल निर्यातक देशों की सूची में शामिल हो गया है।

जनवरी, 2022 में, भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग 375 मिलियन डॉलर (करीब 2700 करोड़ रुपये) का सौदा किया। इस सौदे के तहत भारत शिप-लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति कर रहा है। यह भारत की पहली बड़ी मिसाइल निर्यात डील है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, यूएई, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि देशों को कृ (संभावित ग्राहक) भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की पेशकश की है। ब्रह्मोस के 'लैंड, शिप और एयर वर्ज़न' को लेकर इन देशों में रुचि जताई गई है।

ब्रह्मोस निर्यात भारत की तकनीकी और सामरिक क्षमताओं को दर्शाता है। ब्रह्मोस जैसे हाई-एंड हथियारों के निर्यात से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। साथ ही दक्षिण चीन सागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होती है। इससे 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' की वैश्विक छवि निखर रही है।

भारत का लक्ष्य है कि वह 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इसमें एक प्रमुख स्तंभ बने। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना न केवल विदेशी मुद्रा कमाने का जरिया है, बल्कि यह भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करता है। इससे भारत की 'सॉफ्ट पॉवर' और 'स्ट्रैटेजिक पावर' दोनों को बढ़ावा मिलता है।

डॉ. शशांक द्विवेदी

भारत को आने वाले वक्त में वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी आवश्यकताओं और लॉजिस्टिक्स जैसी चुनौतियों से जूझना होगा। कारगर रणनीतियां और निजी क्षेत्र की सक्रियता इस राह को आसान बना सकती हैं। इनसे निपटने के लिए भारत को अनुसंधान एवं विकास में निवेश, रक्षा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करना होगा।

भारत का डिफेंस सेक्टर अब आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर वैश्विक योगदानकर्ता बनने की ओर अग्रसर है। भविष्य में भारत रक्षा उत्पादों के लिए विश्व का प्रमुख निर्यातक बन सकता है जो न केवल आर्थिक दृष्टि से, बल्कि रणनीतिक रूप से भी देश को वैश्विक मानचित्र पर नई ऊंचाई प्रदान करेगा।

आत्मनिर्भर के संकल्प को साकार करेगा राइज 2025 कॉन्क्लेव

माही की गूंज, रतलाम।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में 27 जून को रतलाम में आयोजित होने जा रहा राइज 2025 कॉन्क्लेव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करेगा। यह आयोजन प्रदेश में उद्यमिता, रोजगार और नवाचार की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनेगा।

मध्यप्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्व-रोजगार आधारित विकास का विजन अब जमीनी स्तर पर साकार हो रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिले, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन, प्रेरणा और सम्मान का भी अवसर मिले ताकि वे नियोक्ता की भूमिका में आगे बढ़ें।

बैतूल के रोहित यादव भी ऐसे ही युवाओं में हैं , जिन्होंने न केवल स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया, बल्कि दूसरों को रोज़गार देने का मार्ग भी प्रशसस्त किया। रोहित को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 11 लाख रुपये का ऋण मिला, जिसमें सरकार द्वारा लगभग 3.5 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई। इस आर्थिक संबल ने उन्हें 'कान्हा मिल्क फूड इंडस्ट्रीज' के रूप में दुग्ध एटीएम व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा दी।

छह डिलीवरी वाहनों और पाँच मिल्क वेंडिंग मशीनों के साथ उनका टर्नओवर अब प्रति माह 9 लाख रुपये से अधिक है और वे 10 अन्य युवाओं को भी प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार दे रहे हैं। नवाचार और गुणवत्ता के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें उपभोक्ताओं के बीच भरोसे का नाम बना दिया है। उन्होंने अपनी डेयरी से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने का कार्य भी शुरू किया है , जिससे आय का अतिरिक्त स्रोत जुड़ गया है।

रोहित का मानना है कि सरकार द्वारा मिली मदद उनके लिए केवल वित्तीय सहयोग नहीं थी , बल्कि यह विश्वास था कि ÷सरकार को हम पर भरोसा है। रोहित मानते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो स्व-रोजगार आधारित सोच विकसित हुई है, उसने हम जैसे युवाओं को आत्मनिर्भरता और गरिमा के साथ जीवन जीने की दिशा दी है। रोहित कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के विजन और इस नीति के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। रोहित यादव जैसे सफल युवा 27 जून को रतलाम में होने वाली राइज 2025 में न केवल सम्मानित होंगे , बल्कि ऐसे अनेक युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी बनेंगे जो प्रयासरत हैं, लेकिन अभी उन्हें दिशा और समर्थन की आवश्यकता है।

राइज 2025 ऐसा मंच बनेगा जो युवाओं के जज्बे, उनके आइडिया और नवीन तकनीक के प्रयोगों को साकार कर समाज एवं प्रदेश को नई पहचान देगा। साथ ही अन्य युवाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। यह मंच कौशल, नवाचार और धैर्य की शक्ति को रेखांकित करेगा। यह कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर युवा को अवसर मिले , हर विचार को उड़ान मिले और हर परिश्रम को पहचान मिले। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग की योजनाएं इसी मंशा को दिशा देती हैं, जहाँ योजनाएं केवल कागज़ पर नहीं, बल्कि व्यवसाय और रोज़गार में तब्दील होती हैं।

कार से कर रहे थे ड्रग्स की तस्करी

माही की गूंज, रतलाम।

जिले की नामली थाना पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 51 लाख रुपए मूल्य की एमडी ड्रग्स जब्त की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने फोरलेन हाइवे पर एक कार से दो तस्करों को गिरफ्तार किया जिनके पास से आधा किलो से अधिक एमडी ड्रग्स बरामद की गई।

एसपी अमित कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि, ये नशीला पदार्थ मंदसौर से लाया गया था और रतलाम में सप्लाई की तैयारी थी। पकड़े गए दोनों आरोपी मंदसौर जिले के रहने वाले हैं और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह एमडी कहां से खरीदी गई थी किसे सप्लाई की जानी थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। इसके लिए खरीद से लेकर वितरण तक की चेन को खंगाला जा रहा है।

रतलाम पुलिस द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स लगातार जिले में नशे के सौदागरों पर कार्रवाई कर रही है और इस अभियान के तहत यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। कार्रवाई में शामिल टीम की सराहना करते हुए एसपी ने कहा कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी और रतलाम जिले को नशे से मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस पूरी सख्ती से काम कर रही है।

सीना ठोककर कह रहा हूं, यहां नहीं रहने दूंगा... जिला पंचायत उपाध्यक्ष

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के शिवगढ़ में एक अजीब घटना हुई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशू निनामा ने थाने में खुलेआम पुलिस को धमकी दी। उन्होंने एसडीओपी के सामने ही थाना प्रभारी को चेतावनी दी। यह सब एक मारपीट के मामले को लेकर हुआ।

एक युवक के साथ हुई थी मारपीट

दरअसल, रतलाम जिले के रामपुरिया गांव में शम्भू सिंह के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर केशू निनामा अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे थे। वहां उन्होंने टीआई को धमकी दी कि अगर सही कार्रवाई नहीं हुई तो वह उन्हें यहां रहने नहीं देंगे।

सीना ठोककर बोल रहा हूं...

केशू निनामा ने गुस्से में कहा कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष टीआई साहब में सीना ठोककर बोल रहा हूं रहने नहीं दूंगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि टीआई साहब, मैं सीना ठोककर कह रहा हूं, मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह कुर्सी तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वह पढ़े-लिखे आदमी हैं और लोगों ने उन्हें वोट दिया है।

वीडियो वायरल

वीडियो में दिख रहा है कि केशू निनामा उंगली उठाकर और सीना ठोककर धमकी दे रहे है। एसडीओपी और अन्य पुलिस अधिकारी चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहे थे। जयस पार्टी के नेता केशू निनामा पुलिस को धमकी देते हुए नजर आए।

प्रदर्शन की धमकी दिया

केशू निनामा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए अपनी धमकी का प्रदर्शन किया। इस घटना से लोगों में गुस्सा है। लोग नेताओं के इस तरह के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं।

फरार हिस्ट्रीशीटर सूर्या को पुलिस ने एमडी ड्रग केस में दबोचा

माही की गूंज, रतलाम/जावरा।

जिले में चल रहे एमडी ड्रग तस्करी केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिस्ट्रीशीटर सुनील उर्फ सूर्या, जो लंबे समय से फरार था। उसे पुलिस ने राजस्थान के उदयपुर से हिरासत में ले लिया है। आरोपी पर कई गंभीर अपराध पहले से दर्ज हैं और वह स्टेशन रोड थाने की गुंडा लिस्ट में भी शामिल है।

200 ग्राम एमडी ड्रग के साथ पकड़े आरोपी

यह मामला 6 मई 2025 का है, जब जावरा-मंदसौर फोरलेन पर पुलिस ने एक स्विफ्ट कार को रोककर दो लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में एक रतलाम का ट्रांसपोर्ट व्यवसायी कमलेश जैन और दूसरा साबिर खान था, जो दलौदा का निवासी है और ऑटो पार्ट्स की दुकान पर काम करता है।

पुलिस को कार से 200 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई थी, जिसकी बाजार कीमत लाखों में बताई जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि यह खेप सुनील सूर्या के कहने पर लाई जा रही थी।

सूर्या की तलाश में बनी थी स्पेशल टीम

कमलेश और साबिर की गिरफ्तारी के बाद से ही हिस्ट्रीशीटर सूर्या की तलाश जारी थी। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसने लगातार सूर्या की गतिविधियों पर नजर रखी। आखिरकार उदयपुर (राजस्थान) में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है।

संभ्रांत लोगों के नाम भी आए सामने

जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि सूर्या से शहर के कई संभ्रांत लोग एमडी ड्रग्स खरीदते थे। यह एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, जिसकी परतें पुलिस खोलने की कोशिश कर रही है। इस केस से जुड़ी कड़ियां मंदसौर और रतलाम जिले के अन्य ड्रग पैडलरों से भी जुड़ सकती हैं।

अवैध नशे के खिलाफ बढ़ी सख्ती

जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस लगातार सक्रिय है। सूर्या की गिरफ्तारी से पुलिस को इस नेटवर्क को तोड़ने में अहम कामयाबी मिली है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की सख्त धाराएं लगाई गई हैं और केस में अब अन्य नामों की पड़ताल की जा रही है।

कुएं में गिर गया बछड़ा, बचाने उतरे 5 लोगों की दम घुटने से मौत

गुना। गुना जिले में एक दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग एक कुएं में गिरे बछड़े को बचाने के लिए नीचे उतरे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इनकी मौत जहरीली गैस, संभवतः कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण दम घुटने से हुई है।

कैसे हुआ हादसा?

जिला कलेक्टर किशोर कन्याल ने जानकारी दी कि यह घटना सुबह करीब 11 बजे घटी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, छह लोग एक कुएं में बछड़े को निकालने के लिए उतरे थे। इनमें से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो को गंभीर हालत में गुना जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकल पाया।

बचाव कार्य में हुई परेशानी

कलेक्टर ने बताया कि कुएं में करीब 12 फीट पानी भरा हुआ था, जिससे बचाव कार्य में भारी दिक्कतें आईं. सीआईएसएफ की गैल यूनिट, एसडीईआरएफ और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक पांच लोगों की जान जा चुकी थी।

बछड़े के पीछे भागते हुए हो गई घटना

ग्रामीणों के अनुसार, यह कुआं एक आम के बाग में स्थित है। मंगलवार की सुबह कुछ ठेके पर काम करने वाले लोग आम तोड़ रहे थे। इसी दौरान एक बछड़ा खेत में आ गया, जिसे भगाने की कोशिश की गई। दौड़ते-दौड़ते वह कुएं में गिर गया। उसे बचाने के लिए ये सभी लोग बारी-बारी से कुएं में उतरते गए और हादसा हो गया।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया

कलेक्टर ने बताया कि, मामले की जांच की जा रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि कुएं में गैस जमा होने के कारण दम घुटा, जिससे मौत हुई।

कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में कालिदास प्रसंग का आज होगा शुभारंभ

माही की गूंज, मंदसौर।

म. प्र. संस्कृति परिषद और कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के माध्यम से 26 ओर 27 जून को कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले कालिदास प्रसंग का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा करेंगे। 26 जून को प्रातः 8:30 बजे भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में कलश पूजा की जाएगी। तत्पश्चात 10:30 बजे प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ कालिदास प्रसंग का शुभारंभ होगा। इस आयोजन में विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर आयोजित श्लोक पाठ एवं भाषण प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार ओर सभी सहभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। सायंकाल 7:00 बजे सांस्कृतिक मंच पर मालवा की लोक परम्परा माच शैली में मेघदूतम लोक नाट्य की प्रस्तुति उज्जैन के कलाकारों द्वारा दी जाएगी। साथ ही मंदसौर नगर की स्थानीय प्रतिभाओं द्वारा संस्कृति के विविध रंग आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी। 27 जून को प्रातः 11 बजे परिसंवाद का आयोजन होगा जिसमें ÷कालिदास के साहित्य में लोकमंगल÷ विषय पर विद्वान वक्तागण डॉ. रघुवीर प्रसाद गोस्वामी भोपाल, डॉ. जे एन त्रिपाठी भोपाल ओर डॉ. किरण आर्या सागर के व्याख्यान होंगे।

ट्रेनों में 25 प्रतिशत से ज्यादा वेटिंग टिकट नहीं, अचानक यात्रा करने वालों को परेशानी

माही की गूंज, रतलाम।

अचानक प्लान बनाकर सफर करने वालों के लिए रेलवे के नए नियम में वेटिंग टिकट मिलना भी मुश्किल भरा हो गया है। हालात यह है कि मुंबई, दिल्ली, पुणे सहित अन्य शहरों के लिए सप्ताह भर आगे भी वेटिंग टिकट नहीं मिल रहा है।

दरअसल, रेलवे में 16 जून से लागू हुआ नया नियम पीक सीजन में उन यात्रियों पर भारी पड़ गया है, जिन्होंने अपनी यात्रा का प्लान अचानक बनाया है या जिनको इमरजेंसी में सफर करना पड़ रहा है।

मुंबई, पुणे, दिल्ली सहित देश के अधिकांश रूटों की ट्रेनों में इस माह के अंत तक रिग्रेट की स्थिति होने के कारण वेटिंग लिस्ट के टिकट नहीं बन पा रहे हैं। रेलवे ने 16 जून से स्लीपर और एसी सहित सभी प्रकार की आरक्षित श्रेणी में सीटों के सापेक्ष वेटिंग लिस्ट के टिकट जारी करने की सीमा 25 प्रतिशत कर दी है।

वेटिंग लिस्ट के टिकट अब नहीं बन रहे

पुणे निवासी संदीप पंड्या व जया पंडया को 27 जून को रतलाम से पुणे जाना है। इंदौर-दौड़ एक्सप्रेस की स्लीपर श्रेणी का आरक्षण का प्रयास किया तो स्थिति रिग्रेट निकली। एसी थर्ड, एसी थर्ड इकोनोमी, एसी सेकेंड तक में टिकट बनाने की कोशिश की, लेकिन सभी में रिग्रेट के कारण वेटिंग लिस्ट के टिकट अब नहीं बन रहे हैं। यह स्थिति आगे के दिनों में भी समान ही दर्शाई जा रही है।

अब जिस श्रेणी में जनरल कोटा, रिमोट लोकेशन कोटा और पूल कोटा में जितनी सीटें होंगी, उसका 25 प्रतिशत तक ही वेटिंग लिस्ट के टिकट जारी होंगे। वेटिंग लिस्ट 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ते ही स्थिति रिग्रेट हो जाएगी। सेंटर आफ रेलवे इन्फारमेशन सिस्टम ने यात्री रिजर्वेशन सिस्टम में यह बदलाव भी कर दिया है।

पीछे के स्टेशनों से बना रहे टिकट

इसका असर यह हो रहा है कि प्रमुख ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मुंबई, पुणे की ओर जाने के लिए रतलाम के पीछे उज्जैन, इंदौर से टिकट लेने पर कुछ ट्रेनों में वेटिंग टिकट मिल रहा है, लेकिन इसके लिए ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। यही स्थिति दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों की भी है। कुछ ट्रेनों में तो 20 से 22 वेटिंग में ही रिग्रेट आप्शन आ रहा है।

कंफर्म टिकट वालों को मिलेगी राहत

ऐसे यात्री जिनके पास कंफर्म टिकट हैं, उनको वेटिंग लिस्ट की सीमा तय होने पर राहत मिल सकती है, हालांकि कोच अटेंडेंट और टीटीई वेटिंग व बेटिकट यात्रियों को आरक्षित बोगियों में सफर कराते हैं। इसकी शिकायतें भी लगातार आ रही हैं।

ऑपरेशन में लापरवाही से महिला की मौत, डॉक्टर पर मामला दर्ज

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा पुलिस ने पम्पुरी अस्पताल के चिकित्सक वाजिद खान के विरुद्ध आपराधिक लापरवाही का प्रकरण दर्ज किया है। डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने किडनी के ऑपरेशन में जरूरी सावधानियां नहीं बरतीं, जिससे मरीज ज्योति ओसवाल की मृत्यु हो गई।

मृतका के परिजनों ने इसकी शिकायत कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से की थी। इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच समिति गठित की गई। जांच में चिकित्सकीय लापरवाही की पुष्टि हुई।

कानूनी विशेषज्ञ रोचक नागौरी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 106(1) (लापरवाही से मृत्यु) के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है।

सीएमएचओ ओ.पी. जुगतावत ने बताया कि डॉक्टर के उपचार से संबंधित जांच कराई गई थी। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।

जरूरी परीक्षण नहीं कराए गए थे

जांच रिपोर्ट में बताया गया कि किडनी ऑपरेशन से पूर्व आवश्यक जांचें - जैसे पेशाब में प्रोटीन, रक्त की मात्रा, और किडनी की कार्यक्षमता - नहीं कराई गईं। इन परीक्षणों के अभाव में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

संक्रमण से हुई मौत

ज्योति ओसवाल निवासी चिनाई रोलड़ी को 21 मई को किडनी की बीमारी के कारण पम्पुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 जून को ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। संक्रमण फैलने पर 16 जून को इंदौर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

डॉक्टर ने कहा था - चार दिन में ठीक हो जाएगी

पति मनोज ओसवाल ने बताया कि डॉक्टर वाजिद खान ने कहा था कि चार दिन में उनकी पत्नी ठीक हो जाएगी। लेकिन ऑपरेशन के बाद ज्योति को चलने में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि दर्द की वजह से ऐसा हो रहा है। धीरे-धीरे स्थिति और बिगड़ती गई।

हंगामा और तोड़फोड़

महिला की मृत्यु की जानकारी मिलते ही परिजन पम्पुरी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की और कांच भी फोड़ दिए। इस पर एसडीएम बजरंग बहादुर, सीएसपी अभिनव बारंगे और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया।

आर्थिक बोझ बना इलाज

परिजनों ने बताया कि उनके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड था, लेकिन पम्पुरी अस्पताल में 50 हजार और इंदौर के अरविंदो अस्पताल में करीब डेढ़ लाख खर्च करवाए गए। आयुष्मान योजना की 5 लाख की सीमा खत्म होने के बाद उन्हें कर्ज लेकर इलाज कराना पड़ा।

मोनालिसा की पड़ोसी किशोरी एक माह से लापता

माही की गूंज, खरगोन।

प्रयागराज कुंभ में माला बेचने के दौरान वायरल हुई मोनालिसा भोसले की पड़ोस में रहने वाली 15 वर्ष की किशोरी पिछले एक माह से लापता है। किशोरी महाराष्ट्र के एदलाबाद में माला बेचने गई थी, वहां से लौटकर नहीं आई। परिजनों ने खरगोन पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा से शिकायत दर्ज कराई है।

परिजनों ने बताया कि किशोरी का मोबाइल बंद आ रहा है। केवल एक बार किसी अनजान नंबर से बात हुई थी, जिसमें जानकारी मिली कि कोई 25 वर्षीय युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। परिजनों को आशंका है कि युवक विवाहित हो सकता है। उसके बाद से किशोरी से कोई संपर्क नहीं हो सका है।

पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि उनकी बेटी को शीघ्र ढूंढ निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि किशोरी की तलाश के लिए पुलिस दल को महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। साथ ही, तकनीकी सहायता के लिए साइबर शाखा से भी मदद ली जा रही है।

पागल कुत्ते ने 13 लोगों को काटा

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले के सिलावद कस्बे में बुधवार को साप्ताहिक हाट-बाजार के दौरान एक पागल कुत्ते ने कहर बरपाया। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच एक घंटे में कुत्ते ने 13 लोगों को काट लिया। हाट में भीड़ अधिक होने के कारण कुत्ता लगातार लोगों पर झपटता रहा।

सभी घायल लोगों को तत्काल सिलावद शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण वाकले ने बताया कि सभी घायलों का उपचार जारी है। एक बुजुर्ग महिला को कुत्ते ने चार बार सिर, हाथ और पैर पर काटा। ग्रामीणों ने कुत्ते को मार गिराया। ग्राम पंचायत सचिव के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही पंचायत कर्मचारियों को कुत्ते की खोज में लगाया गया। कुछ समय बाद ग्रामीणों ने कुत्ते को ढूंढकर मार डाला। यह पहली बार नहीं है जब बड़वानी जिले में ऐसी घटना हुई हो। इससे पहले निवाली, नागलवाड़ी और वरला क्षेत्रों में भी आवारा कुत्तों के हमले हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से खुलेआम घूम रहे पागल कुत्तों को पकड़ने की मांग की है।

होटल में उपयोग कर रहेथे घरेलू सिलेंडर जब्त

माही की गूंज, बुरहानपुर।

यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए राजमार्ग (हाईवे) के किनारे लगने वाले साप्ताहिक हाट-बाजारों को नए स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। नेपानगर के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) भागीरथ वाखला ने इस संबंध में बैठक कर दुकानदारों को समझाइश दी।

बुधवार को एसडीएम वाखला डोईफोड़िया पहुँचे और साप्ताहिक हाट-बाजार के पास खाली पड़ी जमीन का निरीक्षण किया। राजमार्ग पर दुकान लगाने वालों को अपना सामान सड़क के बाहर न रखने की सख्त हिदायत दी गई।

निरीक्षण के दौरान कुछ होटलों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग होता पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए सिलेंडर जब्त कर उन्हें खाद्य विभाग को सौंप दिया गया।

एसडीएम वाखला ने बताया कि कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर यातायात में बाधा बनने वाले हाट-बाजारों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है। डोईफोड़िया साप्ताहिक हाट-बाजार के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर ली गई है। शीघ्र ही ग्राम पंचायत के माध्यम से नया बाजार आरंभ किया जाएगा।

स्थायी दुकानदारों को पहले भी नियमों का पालन करने की चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन कुछ दुकानदार अब भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगली बार नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पति से जान का खतरा, बजरंग दल से मरवाने की धमकी

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन के वार्ड क्रमांक 2 से एआईएमआईएम की पार्षद अरुणा उपाध्याय ने अपने पति श्यामलाल उपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने महिला थाना पुलिस को आवेदन देकर बताया कि उनके पति उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कहकर उन्हें मरवा देंगे। पार्षद ने पुलिस से सुरक्षा की माँग की है।

अरुणा उपाध्याय ने बताया कि उनके मुस्लिम बहुल वार्ड में कई लोगों के काम करने को लेकर पति आपत्ति जता रहे हैं। वह गाली-गलौज करते हैं और नगर पालिका कार्यालय जाने से भी रोकते हैं। बजरंग दल के नाम से धमकी भरे संदेश व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं, जिनके प्रमाण उन्होंने पुलिस को सौंपे हैं। पार्षद का यह भी कहना है कि पति उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हैं।

अरुण उपाध्याय, पार्षद

श्यामलाल उपाध्याय

अरुणा और श्यामलाल की शादी 13 वर्ष पूर्व हुई थी और उनका एक 12 वर्षीय पुत्र है। पार्षद ने बताया कि पिछले दो वर्षों से वैवाहिक संबंधों में तनाव चल रहा है। दो वर्ष पहले भी पति द्वारा मारपीट और जान से मारने की कोशिश की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो इस समय न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पति ने उन्हें बंदूक दिखाकर शादी करने के लिए मजबूर किया था।

अपर पुलिस अधीक्षक शकुंतला रूहल ने जानकारी दी कि पार्षद अरुणा उपाध्याय ने अपने पति के विरुद्ध शिकायत दी है। यह मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद का प्रतीत होता है। महिला थाना पुलिस द्वारा प्रकरण की जाँच प्रारंभ कर दी गई है।

श्यामलाल उपाध्याय ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें कुछ गतिविधियाँ संदेहास्पद लगी थीं, इसलिए उन्होंने पति होने के नाते समझाने का प्रयास किया था। उनका कहना है कि वे सभी आरोपों का उत्तर उचित स्थान पर देंगे।

अरुणा उपाध्याय ने एआईएमआईएम के टिकट पर वार्ड क्रमांक 2 से नगर निकाय चुनाव जीतकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराया था। वे एआईएमआईएम की प्रदेश में पहली हिंदू महिला पार्षद हैं। उन्होंने बारहवीं तक शिक्षा प्राप्त की है और सौंदर्य प्रसाधन का पाठ्यक्रम भी पूरा किया है।

बिजली के टूटे तार ने ली किसान की जान, दो महिलाएं घायल

माही की गूंज, बड़वानी। जिले के ठीकरी थाना क्षेत्र के नार मंबुपवार गांव में दोपहर के समय खेत से लौट रहे किसानों की बैलगाड़ी पर बिजली का तार गिर गया। इस हादसे में किसान फिरोज खान की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि करंट की चपेट में आकर एक बैल की भी मौत हो गई। हादसे में साथ मौजूद महिलाएं - जायदा बाई और देवकी बाई घायल हो गईं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

घायल देवकी बाई ने बताया कि वे खेत से निराई करके लौट रहे थे। जब वे नाला पार कर रहे थे, तभी बिजली का तार पोल से टूटकर सीधे बैलगाड़ी पर गिर गया। डॉ. पाटीदार के अनुसार, दोनों घायल महिलाओं का उपचार किया जा रहा है। मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

फेक नैरेटिव के दौर में सिसकती इंसानियत

इस्राइल-ईरान युद्ध के खात्मे का इंतजार दुनिया को था कि विश्व का दरोगा अमेरिका इसमें कूद पड़ा। दुनिया पहले ही रूस-यूक्रेन युद्ध से परेशान थी, इस बीच भारत-पाकिस्तान के बीच भी कुछ दिनों का युद्ध हो चुका था। अमेरिका का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है। ईरान पर बम बरसाने से पहले अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि वह फौरन इसे रोके। यह बात बिल्कुल ठीक है कि परमाणु अस्त्र पूरी मानवता के लिए आफत की तरह हैं। जापान के हिरोशिमा-नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, उनकी विनाशक क्षमता आज के परमाणु हथियारों के मुकाबले बहुत कम थी। तब भी जापान ने इसे दशकों तक भुगता। आज तो ऐसे हथियार हैं, जो पल भर में दुनिया को खत्म कर सकते हैं। ऐसे में हे अमेरिकियों, जितने मारक हथियारों के जखीरे आपके पास हैं, दूसरे देशों को उपदेश देने से पहले, उन्हें नष्ट क्यों नहीं कर देते। क्या वे दुनिया के लिए खतरा नहीं हैं....या कि उसी तर्क पर चलते हो कि जबरा मारे और रोने भी न दे।

जब अमेरिका के खिलाफ ये बातें की जा रही हैं, तब इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि ईरान का पक्ष लिया जा रहा है। मानव अधिकारों के मामले में ईरान की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। दशकों पहले जब ईरान के इस्लामिक आंदोलन ने शाह रजा पहलवी को खदेड़ दिया था और पेरिस में निर्वासित जीवन बिताने वाले खोमेनी को हाथो हाथ लिया था, तब की याद आती है। खोमेनी के पक्ष में वहां जो युवा शाह के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, उनमें से बहुत से खुद को इस्लामिक मार्क्सिस्ट कहते थे। जब खोमेनी पेरिस से लौटे, तो उनकी कार को कंधे पर उठा लिया गया था। बाद में सबसे पहले खोमेनी ने इन्हीं इस्लामिक मार्क्सिस्ट कहने वाले लोगों को सरेआम मौत के घाट उतरवाया था। शाह ने स्त्रियों को घर की चारदीवारी से निकाला था, उन्हें आत्मनिर्भरता की राह दिखाई थी, खोमेनी ने उन्हें वापस सदियों पहले की स्थिति में धकेल दिया।

अब वहां स्त्रियां अपने आप कुछ नहीं कर सकतीं। न बैंक अकाउंट खोल सकती हैं, न बिना माता-पिता की लिखित अनुमति के पढ़ सकती हैं, न नौकरी कर सकती हैं। न शादी ही। सिर से हिजाब जरा-सा खिसका नहीं कि आफत आई नहीं। अफगानिस्तान की तरह ही वहां भी स्त्रियों को मामूली मानव अधिकार नहीं हैं। इसे धर्म और हमारी संस्कृति कहकर रफा-दफा कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका जिसका ट्रेक रिकॉर्ड दुनिया भर के तानाशाहों को पालना-पोसना रहा है, वह मनमाने तरीके से मानव अधिकारों की व्याख्या करता है। चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकंस, उनकी नजर सिर्फ अपने यहां पूंजीपतियों के हितों को देखने की होती है। मानव अधिकार आदि की बातें तो दुनिया को दिखाने के लिए होती हैं।

इस सिलसिले में जान पर्किन्स की मशहूर पुस्तक 'कन्फेशन्स ऑफ़ ऐन इकोनॉमिक हिटमैन' पढ़ी जा सकती है। जान खुद इकोनामिक हिटमैन रहे हैं यानी कि दूसरे देशों में अमेरिकी पूंजीपतियों के हितों को हर हाल में संरक्षित करने वाले।

फिर दूसरा देश अपने यहां क्या करना चाहता है, इसमें दखल देने वाले आप कौन हैं। अमेरिका अपने यहां कौन से हथियार विकसित कर रहा है, यदि किसी दूसरे देश को यह बात पसंद न आए तो क्या वह अमेरिका पर उसी तरह हमला कर दे, जैसे अमेरिका करता है। कल अगर भारत की सत्ता आपकी बात न माने, तो आप उस पर भी चढ़ दौड़ेंगे। ये बात अलग है कि कभी वियतनाम से पिटेंगे, तो कभी अफगानिस्तान से सिर पर पांव रखकर भागेंगे।

आपको नब्बे का दशक याद होगा। अमेरिका, ईराक पर टूट पड़ा था। बहाना बनाया था कि ईराक के पास ऐसे रासायनिक हथियार हैं, जो विश्व को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि यह कभी प्रमाणित नहीं हो सका। लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उनका वह चित्र छपा था, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनका सिर एक ओर पड़ा था और धड़ एक ओर।

नब्बे के दशक में ही भारत में टेलीविजन घर-घर पहुंच चुका था। ईराक, अमेरिका की लड़ाई का पहली बार लाइव प्रसारण लोगों ने घर बैठकर देखा था और रोमांचित हुए थे। आज इक्कीसवीं सदी के पचीसवें वर्ष में इस्राइल, अमेरिका, ईरान युद्ध की तस्वीरें, लाइव प्रसारण भी खूब दिख रहे हैं।

बीबीसी और न्यूयार्क टाइम्स ने बताया कि इस समय युद्ध के फेक वीडियोज और रील्स की बाढ़ आ गई है। इन्हें एआई द्वारा तैयार किया गया है। इन रील्स और वीडियोज को देखने वालों और फालोअर्स की संख्या करोड़ों में पहुंच रही है। इस फेक नैरेटिव से लड़ना वाकई मुश्किल काम है। इसे 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय भी देखा गया था। किस तरह से पश्चिमी मीडिया ने भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव तैयार किया था। लिखने वाले पाकिस्तानी और छपने वाले यही न्यूयार्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, टेलीग्राफ, बीबीसी आदि ही थे। लेकिन अब जब अमेरिका, इस्राइल के खिलाफ फेक वीडियोज और रील्स भारी पैमाने पर आने लगे, तो रोने लगे। पश्चिमी मीडिया ऐसा ही दुरंगा है। अपने मालिकों को हर हाल में बचाता है। उनके खिलाफ शायद ही कभी मानव अधिकार हनन का रोना रोया जाता है। इसमें पश्चिमी न्यूज एजेंसीज भी बढ़-चढ़कर भूमिका निभाती हैं। तरह-तरह के गढ़े झूठ को सच की तरह परोसा जाता है।

अपने यहां भी अधिकांश चैनल्स जिस तरह का युद्धोन्माद भड़का रहे हैं, वह काफी निंदनीय और चिंतित करने वाला है। ज्यादा से ज्यादा टीआरपी और उसके बदले विज्ञापनों की बढ़त के कारण हर समय ऐसेदृऐसे हैडिंग्स लगाए जा रहे हैं- इस्राइल ईरान क्रुद्ध, अब होगा विश्वयुद्ध। या कि नहीं रुकेगा परमाणु युद्ध। आश्चर्य यह होता है कि यदि परमाणु युद्ध हो जाए, तो क्या वे लोग बचे रहेंगे, जो इस तरह की भविष्यवाणियां रात-दिन करके माल बटोर रहे हैं। आपने ईरान की उस टीवी पत्रकार की हालत तो देखी ही होगी, जो स्टूडियो पर इस्राइली हमले के बाद लाइव प्रसारण छोड़कर भागी।

क्षमा शर्मा

ईरान के खामनेई अक्सर कहते रहे हैं कि वे इस्राइल का नामोनिशान मिटा देंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता, तो इस तीन साल से अधिक के वक्त में रूस ने यूक्रेन का नामोनिशान मिटा दिया होता। इस्राइल के खिलाफ तो इतने अधिक देश हैं कि वह कब का खत्म हो गया होता। लेकिन इन दिनों न कोई युद्ध जीतता है, न हारता है। दोनों ही पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता है। हां तीसरी पार्टियां अगर बीच में आ जाएं, तो यह नुकसान और बढ़ जाता है। जो रील्स और वीडियोज देखे हैं, उनमें ईरान की विजय पर माशा अल्लाह और देख लो इस्राइल की हालत आदि बड़े पैमाने पर हैं। इसी तरह के वीडियोज इस्राइल से भी आ रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। अच्छा तरीका तो यही है कि जहां भी लड़ाई हो रही है, वह रुके। इस दुनिया में पहले ही आफतें क्या कम हैं। आम लोगों की किसी भी लड़ाई में शायद ही कोई भूमिका होती है, लेकिन बड़ी संख्या में मारे वे ही जाते हैं।

स्कूल से लौट रही छात्राओं के पास आकर रूकी बिना नंबर की कार

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के ग्राम धतुरिया निवासी चार छात्राएं मंगलवार दोपहर ग्राम दीपाखेड़ा से स्कूल से लौट रही थीं, तभी बिना नंबर की कार छात्राओं के पास आकर रुकी एवं वाहन में सवार चार युवकों ने छात्राओं को गाड़ी के अंदर खींचकर बैठाने का प्रयास किया।

इस दौरान एक छात्रा ने भागकर खेतों में बोवनी कर रहे ग्रामवासियों को जानकारी दी। कुछ ही देर में आसपास के खेतों से लोग पहुंच गए। इस दौरान लोगों को देख कार सवार तीन युवक भाग निकले।

आरोपित जितेंद्रसिंह निवासी रुडी (उज्जैन) को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जितेंद्र नशे में था एवं कार में कई अन्य युवतियों के आधार कार्ड व नशे से जुड़ी सामग्री भी पड़ी थी। इसे देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए।

ग्रामीणों ने कार में लगा दी आग

सूचना पर सीतामऊ पुलिस पहुंची। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों से तीन अन्य आरोपितों को तुरंत पकड़ने की मांग की। इसी बीच कुछ आक्रोशित लोगों ने कार में आग लगा दी। इसके बाद मौके पर स्थिति बिगड़ने लगी।

उज्जैन जिले का रहने वाला है आरोपी

सीतामऊ एसडीओपी दिनेश प्रजापति, थाना प्रभारी मोहन मालवीय सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। आरोपित को गिरफ्तार कर सीतामऊ थाने लाया गया, जहां मामले में प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपित जितेंद्रसिंह निवासी रुडी (उज्जैन) को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया हैं।

अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। घटना में पकड़ी गई कार पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी।

नशे में धुत महिला टीचर पहुंची स्कूल, स्टाफ से करने लगी अभद्रता

माही की गूंज, धार।

जिले से शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां सरकारी स्कूल में पदस्थ महिला टीचर नशे की हालत में स्कूल पहुंच गई और वहां मौजूद स्टाफ से बदसलूकी की। यह घटना 23 जून को मनावर विकासखंड के सिंगाना गांव स्थित एक एकीकृत विद्यालय में हुई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और शिक्षिका को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।

ट्राइबल एजुकेशन विभाग के सहायक आयुक्त नरोत्तम वरकड़े ने बताया कि, वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर किशोर कुमार को जांच के निर्देश दिए। बीआरसी और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की संयुक्त टीम ने इस मामले की प्राथमिक जांच की और रिपोर्ट सौंपते ही महिला टीचर को निलंबित कर दिया गया।

नशे में धुत होकर स्कूल पहुंची शिक्षिका ने न सिर्फ स्कूल स्टाफ से बदतमीजी की, बल्कि स्कूल में काम कर रहे मजदूरों से भी अभद्र भाषा में बात की और हंगामा कर दिया।

अधिकारी नरोत्तम वरकड़े ने बताया कि, इस मामले में विभागीय जांच शुरू की जा रही है, जिसके बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह का अमर्यादित और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभिभावकों और ग्रामीणों में इस घटना को लेकर नाराज़गी देखी जा रही है और वे महिला शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

महाकाल दर्शन करने गए युवक की शिप्रा नदी में डूबने से मौत

माही की गूंज, उज्जैन।

महाकाल दर्शन करने दोस्तों के साथ आए भोपाल के युवक की बुधवार सुबह शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। वह मंदिरों में देव दर्शन करने के बाद शिप्रा नदी में नहाने गया था, जहां गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई।

मौके पर मौजूद तैराक दल और होमगार्ड के जवानों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया गया।

मां शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने बताया कि, 16 वर्षीय समीर मीणा भोपाल के इमलिया क्षेत्र का रहने वाला था। वो अपने छह दोस्तों के साथ महाकाल मंदिर सहित अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए उज्जैन आया था। बुधवार सुबह समीर सभी दोस्तों के साथ शिप्रा नदी पर स्थित सिद्ध आश्रम के पास घाट पर पहुंचा। यहां सभी लोग नदी में डुबकी लगाकर स्नान करने लगे। इस बीच समीर गहरे पानी में चला गया। युवक को डूबता हुआ देखकर उसके दोस्तों के शोर मचाने लगे। शोर सुनकर मौके पर मौजूद तैराक दल के तेजा कहार, पप्पू कहार, दीपक कहार, बड़ा हुकुम कहार, मन्नू कहार, राज कहार, हुकुम ठाकुर, रूपसिंह कहार, माधव सिंधे, दिनेश कहार, जितेंद्र कहार और होमगार्ड के जवानों ने उसकी तलाश शुरू की। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। इसके बाद समीर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच उपरांत डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

लोन के रुपए जमा करने के नाम पर युवती से 7 लाख की ठगी

माही की गूंज, उज्जैन।

लोन के रुपए जमा करने के नाम पर एक युवती से सात लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। युवती ने एक कंपनी से ऑनलाइन लोन लिया था। कंपनी ने उसे सात लाख रुपये लोन दिया था।

युवती ने कुछ समय बाद लोन के सात लाख रुपए जमा करवा दिए थे। मगर कंपनी के कर्मचारी ने अपने बैंक खाते में रुपये जमा करवा लिए थे। मामले में चिमनगंज पुलिस ने केस दर्ज किया है।

7 लाख लोन देने पर नहीं हुई ईएमआई बंद

टीआइ गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि नेहा ठाकुर निवासी तिरुपति धाम कॉलोनी ने मार्च में निजी फाइनेंस कंपनी से सात लाख रुपये लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। वेरिफिकेशन के लिए युवती के घर कंपनी का एक कर्मचारी विकास कुमार निवासी उत्तम नगर दिल्ली आया था। लोन लेने के कुछ समय बाद युवती ने पूरा लोन चुकाने के लिए वेरिफिकेशन के लिए आए विकास को सात लाख रुपये का चेक दे दिया था। मगर इसके बाद भी उसकी ईएमआइ बंद नहीं हुई थी।

आरोपी ने अपने खाते में जमा किए पैसे

युवती ने कंपनी के कार्यालय से इसकी जानकारी ली तो पता चला था कि लोन के रुपये उसके खाते में जमा ही नहीं हुए हैं। विकास कुमार ने रुपये अपने बैंक खाते में जमा कर लिए थे। युवती ने विकास से चर्चा की तो उसने बताया कि रुपये उसने खर्च कर दिए हैं। जिसके बाद युवती ने चिमनगंज पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है।

अर्धनारीश्वर रूप में बेटे को लेकर कोर्ट पहुंचा पिता

आगर मालवा।

प्रदेश के आगर मालवा कोर्ट परिसर में सोमवार को उस समय सभी की निगाहें एक शख्स पर टिक गईं जब वह अर्धनारीश्वर के रूप में अपने बेटे के साथ आत्मसमर्पण करने पहुंचा। आरोपी की पहचान मनोज बामनिया के रूप में हुई है जो अपने ढाई साल के बेटे भव्यांश के अपहरण के मामले में पिछले तीन महीने से फरार था।

मनोज ने कोर्ट में पेश होकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वह आधे शरीर पर पैंट-शर्ट और आधे पर साड़ी व चूड़ियां पहने हुए था। माथे पर आधी बिंदी भी थी। उसने कहा कि, यह रूप उसने इसलिए अपनाया ताकि समाज को बता सके कि एक पिता भी अपने बच्चे के लिए उतनी ही ममता रखता है जितनी एक मां।

बेटे के अपहरण के मामले में पिता ने किया आत्मसमर्पण

मनोज ने बताया कि, वह पेशे से फैशन डिजाइनर है और अपहरण के बाद से बेटे को लेकर इंदौर, सूरत और मुंबई में रहा। भव्यांश के अपहरण की घटना 16 मार्च को हुई थी जब उसकी मौसी रोशनी उसे मंदिर ले जा रही थी और बोलेरो गाड़ी से आए लोगों ने बच्चे को उठा लिया।

पुलिस ने आरोपी पिता की तलाश में इनाम घोषित किया था

पुलिस ने मनोज की तलाश में इनाम घोषित किया था और अब वह खुद कोर्ट पहुंचा।

मनोज और उसकी पत्नी रीना पिछले दो साल से अलग रह रहे हैं। रीना ने उस पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था और बच्चे की सुपुर्दगी मां को दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने मनोज को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

माही की गूंज, अलीराजपुर।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाटीदार ने बताया कि, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर अनीष कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीनाथ नर्सिंग कॉलेज में किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में जय पाटीदार ने नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीडितों के लिये विधिक सेवाऐं) योजना 2015 की जानकारी दी ताकि उन्हें न्याय मिल सके और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए उन्हें मुआवजा मिल सके। पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान, महिलाओं संबंधी श्रम विधि, लिंग परीक्षण प्रतिषिद्धता, महिलाओं के गिरफ्तारी पर प्राप्त अधिकार आदि की विस्तृत जानकारी दी गई।

रेलों से सिंहस्थ कुंभ में पहुंचेंगे एक करोड़ श्रद्धालु

माही की गूंज, उज्जैन।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2028 के दौरान उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले में शामिल होने के लिए करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं के रेल से सफर करने का अनुमान है और इन यात्रियों की सुविधा के लिए 100 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। सिंहस्थ कुंभ मेला भगवान शिव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग वाली धार्मिक नगरी उज्जैन में हर 12 साल के अंतराल में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है।

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कुमार ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, '(वर्ष 2016 के दौरान आयोजित) पिछले सिंहस्थ कुंभ मेले में करीब 20 लाख लोग रेल से सफर करके उज्जैन पहुंचे थे। हमारा अनुमान है कि 2028 के सिंहस्थ मेले में यह तादाद पांच गुना बढ़कर एक करोड़ के आस-पास पहुंचने वाली है।' रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 3 साल बाद लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान यात्रियों के सैलाब को संभालने के लिए उज्जैन के साथ ही इंदौर, महू, लक्ष्मीबाई नगर और आस-पास के अन्य रेलवे स्टेशनों को तैयार किया जा रहा है।

संबल एवं अनुग्रह के लंबित प्रकरणों का शिविर लगाकर निराकृत करें-कलेक्टर

माही की गूंज, धार।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में ली गई। जिसमें मनरेगा, जल गंगा संवर्धन अभियान (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना, जिला खनिज प्रतिष्ठान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम पोषण योजना, 15वें वित्त के कार्य एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति (ग्रामीण) की समीक्षा की गई। कलेक्टर द्वारा श्रमिक नियोजन एवं लेबर बजट उपलब्धि की समीक्षा कर जिन विकासखण्डों में अंतर पाया गया, उन्हें कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। वर्ष 2025-26 व पूर्व तीन वर्षों के अपूर्ण कार्यों की समीक्षा कर समस्त विकासखण्डों को दिए गए लक्ष्य प्राप्ति हेतु रणनीति बनाकर कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। मनरेगा अंतर्गत आरईएस विभाग के कार्यों की समीक्षा कर आरईएस से खराब प्रगति का कारण पूछे जाने पर आरईएस द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे कार्य जो पूर्ण तो हो चुके है, लेकिन उनका पेमेंट नहीं हुआ है, उसकी जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत पंजीयन की समीक्षा की गई। इस योजना अंतर्गत कुल 99 हजार 422 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 83.41 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण किया गया। जॉच अधिकारी स्तर पर लंबित प्रकरणों का निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। संबल योजना अंतर्गत 180 दिवस उपरांत अनुग्रह सहायता के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। 134 प्रकरण लंबित पाए गए। लेबर अधिकारी द्वारा विभाग से समन्वय कर कार्य नहीं किए जाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा कहा गया कि प्रायः यह पाया जाता है कि जनपद पंचायतों में रिकार्ड व्यवस्थित नहीं होते है। इस हेतु जनपद एवं जिला पंचायत स्तर पर रिकार्ड व्यवस्थित किए जाने के साथ ही समस्त कार्यवाही/पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से किए जाएं। संबल पोर्टल पर अनुग्रह सहायता राशि के 220 प्रकरण लंबित पाए गए। जिनमें सर्वाधित लंबित प्रकरण सरदारपुर में पाए गए। कलेक्टर द्वारा कहा गया कि समय सीमा वाले कार्यो को बेवजह लंबित न रखे। संबल योजना अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन पर एल-1, एल-2, एल-3 स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई।

क्या जनसुनवाई का नाम अब बन सकता है आर्थिक सहायता केंद्र...?

माही की गूंज, झाबुआ।
मुज्जमील मंसुरी

वैसे तो जनसुनवाई आमतौर पर आमजन की समस्याओं के लिए प्रदेश सरकार ने कई वर्षों पहले शुरू की थी। सरकार यह योजना लगातार अब भी बदस्तूर जारी है। जनसुनवाई के शुरूआती दौर से लेकर इसमें आमजन प्रशासनिक समस्याओं, जमीन विवादों, राशन कार्ड, विद्युत बिल, बैंक लेन-देन, अवैध कब्जों और इस तरह की तमाम समस्याओं के लिए जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाते दिखाई देते थे। हालांकि सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि, हर विभाग के कार्यालय में जनसुनवाई हो लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसीलों व पंचायत स्तर तक इस योजना के महज बोर्ड और सूचनाएं ''जनसुनवाई हर मंगलवार दोपहर 11 बजे से'' ही कार्यालयों में दिखाई दिए है। मगर इस तरह का कोई आयोजन अब किसी कार्यालय में होता नजर नहीं आता। झाबुआ जिले की अगर बात करें तो अब सिर्फ जिला मुख्यालय पर कलेक्टोरेट कार्यालय में ही इस जनसुनवाई का आयोजन होता दिखाई देता है। कुछएक तहसील कार्यालयों में भी इसका संचालन होता है। मगर नियमित्ता का अभाव है। सिक्के का दूसरा पहलू यह कि, ग्राम पंचायतों से लेकर तहसील स्तर पर होने वाली जनसुनवाईयों में आवेदकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इसलिए आवेदक अब सीधे तौर पर जिला मुख्यालय और कलेक्टर कार्यालय का रूख करते है। नतीजा यह सामने आता है कि, मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में सैकड़ों आवेदकों की भीड़ नजर आती है।

प्रशासनिक समस्याओं, जमीन विवादों, राशन कार्ड, विद्युत बिल, बैंक लेन-देन, अवैध कब्जों और इस तरह की तमाम समस्याओं के लिए अब तक इस जनसुनवाई में आवेदक, शिकायत करते थे। लेकिन अब जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग आर्थिक सहायता के लिए आवेदन लेकर पहुंच रहे है। जनसुनवाई में आने वाले इस तरह के आवेदकों की संख्या दहाई के आंकड़े तक पहुंच रही है। इन आवेदकों द्वारा दिए गए आर्थिक सहायता आवेदनों में अधिकतर पारिवारिक व आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होना बताया जा रहा है। जिन्हे बकायदा कलेक्टर कार्यालय से आर्थिक सहायता मिल भी रही है।

सरकार और प्रशासन के दावों की खुलती पोल

अब सवाल यह उठता है कि, सरकार की तमाम तरह की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद जिले में इस तरह से लोगों का आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करना सरकार और प्रशासन की तमाम काशिशों को धत्ता बता रही है। वैसे तो जिले में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। जिसमें मुख्य रूप से लाडली बहना योजना है। जिसमें महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। इसके अलावा राशन योजना के तहत ग्रामीणों को अनाज, धान और शक्कर जैसी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा आयुषमान योजना के तहत 5 लाख का इलाज भी मुफ्त सरकार की ओर दिया जाता है। संबल योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल-जल योजना, और भी ऐसी कई योजनाएं है जिससे ग्रामीण व गरीब जनता की सरकार भर पल्ले मदद करती है। बावजूद इसके अगर जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में आर्थिक सहायता के आवेदन पहुंच रहे है तो यह कई तरह के सरकारी दावों और जिला प्रशासन की कार्यशैली व उसके दावों की पोल ही खोलता नजर आता है।

इस तरह कलेक्टर दे सकते है आर्थिक सहायता

वैसे तो जिला कलेक्टर विभिन्न तरीकों से आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं, खासकर प्राकृतिक आपदाओं या संकट की स्थिति में। वे प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए धन, खाद्य सामग्री, और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि किसानों को ऋण माफी या विधवा पेंशन।

अगर इसे विस्तार से समझे तो कलेक्टर, जिले

में आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में, प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा) से प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास कार्यों का नेतृत्व करते हैं। कलेक्टर निम्नलिखित तरीकों से आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं।

आपदा राहत कोष

कलेक्टर आपदा राहत कोष से धन आवंटित कर सकते हैं ताकि प्रभावित लोगों को भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा सकें।

सरकारी योजनाएं

वे विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं।

ऋण माफी

किसानों को ऋण माफी प्रदान करने के लिए, कलेक्टर संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, खासकर जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें खराब हो जाती हैं।

विधवा पेंशन

विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, कलेक्टर विधवा पेंशन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि, पात्र विधवाओं को कल्याणी योजना के तहत समय पर पेंशन मिले।

अन्य सहायता

कलेक्टर प्रभावित लोगों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि, चिकित्सा व्यय के लिए सहायता, या व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण।

संक्षेप में, कलेक्टर जिले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से आपदाओं के समय, और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं।

भ्रष्टाचार के कारण अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती योजनाएं?

सरकार की योजनाओं की बात करें तो इनकी संख्या इतनी है कि, अगर एक आम आदमी इन सारी योजनाओं का लाभ उठा सके तो उसे किसी भी तरह के आर्थिक परेशानी हो ही नही सकती, मगर ऐसा हो नहीं पाता। इसका सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी कहा जा सकता है, जो आमजन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में नाकाम साबित होते है।

दूसरा और सबसे बड़ा कारण सरकारी योजनाओं में तंत्र के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक भ्रष्टाचार की गंगा में डूबकी लगाते नजर आते है। मतलब गरीबों के विकास और समृद्धी के लिए मिले पैसे की खूब बंदरबांट होती है और विकास गरीबों का होने के बजाय तंत्र में बैठे बागड़ बिल्लों का हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण जिले में देखने को मिलते है जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। मगर उसके बाद न तो गबन हुई राशि आज तक किसी केश में वापस बरामद की गई और ना ही गरीबों का हक उन तक पहुंचाने की कवायद। नतीजा यह निकलकर सामने आया कि, जिले का गरीब और आदिवासी आज भी फटेहाल जीवन जीने को मजबूर है। यही मजबूरी उन्हे कलेक्टर के सामने जनसुनवाई में आर्थिक सहायता की गुहार लगाने को मजबूर कर रही है।

महज दो माह में 5 लाख 65 हजार की आर्थिक सहायता

मई और जून माह की स्थिति पर अगर नजर डाली जाए तो यह समझ आता है कि, स्थिति कितनी खराब है। कलेक्टर की जनसुनवाई में महज मई और जून माह में करीब साढ़े 5 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता लोगों को दी गई। अब तो आलम यह है कि, हर जनसुनवाई में एक दर्जन से अधिक लोग सिर्फ आर्थिक सहायता का आवेदन लेकर पहुंच रहे है। पीआरओ कार्यालय से जारी आंकड़ों के अनुसार 6 मई की जनसुनवाई में 40 हजार की आर्थिक सहायता कलेक्टर द्वारा दी गई। इसके बाद 13 मई को 85 हजार, 20 मई को 55 हजार, 27 मई को 50 हजार, 3 जून को 40 हजार, 10 जून को 1 लाख 10 हजार, 17 जून को 1 लाख 10 हजार और 24 जून को 75 हजार की आर्थिक सहायता कलेक्टर द्वारा विभिन्न आवेदकों को दी गई। कुल मिलाकर मई और जून का जनसुनवाई में दी गई आर्थिक सहायता का आंकड़ा 5 लाख 65 हजार तक पहुंच गया।

आर्थिक सहायता क्या समस्या का समाधान...?

हालांकि प्रशासन की कोई तो गाइड लाइन होगी जिसके तहत इस तरह से हर जनसुनवाई में दर्जनों लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। उम्मीद तो यही है कि, लाखों रुपये की यह आर्थिक सहायता सही व जरूरतमंद लोगों को मिल रही होगी। मगर इस तरह की आर्थिक सहायता क्या समस्या का स्थाई समाधान हो सकती है...? अगर इसी तरह आर्थिक सहायता के लिए आवेदनों की संख्या जनसुवाई में बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब जनसुनवाई कार्यक्रम का नाम बदल कर आर्थिक सहायता केंद्र रखना पड़ जाए।

सहायता के पहले जांच जरूरी

इसके उलट कलेक्टर को चाहिए कि, आवेदक की आर्थिक स्थिति की पूर्ण रूप से जांच करे या करवाएं। आर्थिक सहायता देने की बजाए उसके आर्थिक स्त्रोतों को बढ़ाने की ओर पहल करें। गरीबी और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार के लिए विकल्पों की आवष्यकता होती है ना कि, कुछ हजार की आर्थिक मदद की। इसके अलावा जिस तरह से जनसुनवाई में आवेदन आर्थिक सहायता के लिए पहुंच रहे है उनकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में यह देखने में आया है कि लोग एक -दूसरे को देखकर आवेदन लेकर जनसुनवाई में पहुंच जाते है और उन्हे आर्थिक मदद मिल जाती है।

यह मामले पर लगाता है ...?

एक ऐसा ही मामला संज्ञान में आया जिसमें पता यह चला कि, एक व्यक्ति बीमार था उसने अपना इलाज अपने खर्च पर करवाया और वह ठीक हो गया। जिसके बाद वह पूरे आठ माह के लिए गुजरात मजदूरी करने पहुंच गया। जब आठ माह बाद वह वापस आया तो उसकी तबीयत फिर खराब हो गई। अब उसने फिर से ईलाज लेना शुरू कर दिया। जिस आयुर्वेदिक उपचार पद्धति से वह उपचार ले रहा है वह काफी प्रभावी और सस्ती है। गुजरात में आठ माह तक मजदूरी कर लौटने वाले की आर्थिक स्थिति इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि, वह अपना इलाज ना करवा सके। जबकि कोई गंभीर बीमारी भी न हो। मगर उक्त व्यक्ति की पुत्री ने जनसुनवाई में आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला दे कर आवेदन दिया और कलेक्टर महोदय ने उसे तुरंत ही 15 हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी। यह सारा माजरा हसते हुए व्यक्ति की पुत्री ने किसी चर्चा के दौरान सुनाया और उसकी आवाज का उत्साह बता रहा था कि, वह फिर से इसी तरह की आर्थिक सहायता लेने दौबारा कलेक्टर के सामने पहुंच जाएगी।

रतलाम-झाबुआ पर बने पुलों की रेलिंग दे रही बड़ी दुर्घटनाओ को निमंत्रण

कई स्थानों पर रोड की स्थिति खराब, नये रोड के कार्य कछुवा गति से जारी

लाड़की नदी की जर्जर रेलिंग।

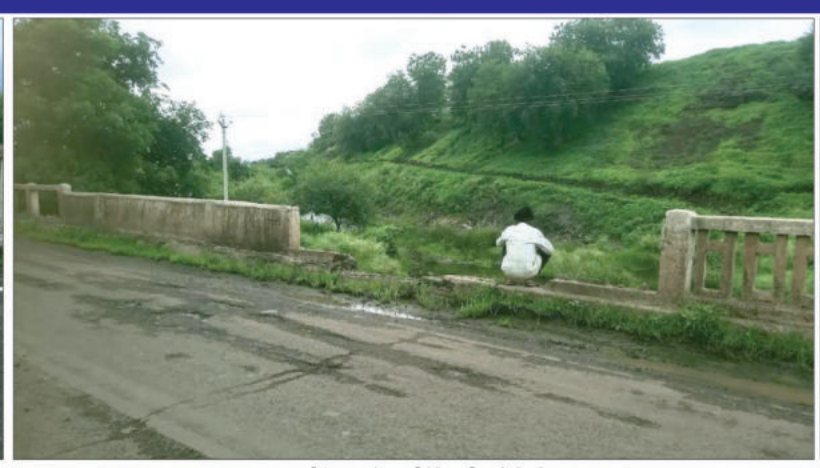

ग्राम घुघरी के पास बने पुल की रेलिंग की जर्जर स्थिति।

माही नदी पर बने पुल की जर्जर स्थिति।

माही की गूंज, पेटलावद।

मध्यप्रदेश सरकार की और से उज्जैन में आने वाले सिंहस्थ में जुटने वाली भीड़ देखते हुए सिंहस्थ पहुँचने के मुख्य मार्गो को दुरुस्त करने एवं नवीन निर्माण पर जोर दे रही है। कई मार्गो की चौड़ाई बड़ाई गई तो कई मार्ग फोर लेन में भी तब्दील कर दिए गए। नये रोडो के स्वीकृत होने के बाद वर्तमान में बनी सड़को की देख रेख बंद कर दी। नई सड़को का कार्य शुरू तो हुआ लेकिन कछुआ गति से काम चलने की स्थिति में वाहन चालको को भारी परेशानीया का सामना करना पड़ रहा है और आये दिन वाहन दुर्धटनाओ का शिकार हो रहे हैं। झाबुआ-रतलाम मार्ग पर बने पुलों की रेलिंग की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि अगर वाहन थोड़ा सा भी अनियंत्रित हुआ तो सीधा नदी में समा जाएगा ।

छोटे बड़े पुलों की रेलिंग की हालत खराब, वर्षो पुरानी रेलिंग कई जगह से टूटी

रतलाम-झाबुआ मार्ग पर स्थित लाड़की और माही नदी जैसे बड़े पुल सहित करवड़ से रानीसिग के बीच बने छोटे पुलों की रेलिंग की स्थिति इतनी भयावह हो चली है कि पुलों से गुजरने वाले छोटे-बड़े वाहनों को दुर्घटना का भय बना रहता है, खास कर पूल पर वाहन क्रासिंग होती है जब दुर्धटना का भय और भी बढ़ जाता है। इन पुलों की रेलिंग पूरी तरह से जर्जर होकर कई स्थानों पर टूट कर बिना रेलिंग के पुल की स्थिति बन गई है। ग्राम करवड़, घुघरी के पास बने पुलों की भी यही स्थिति है। इस मार्ग के निर्माण के दौरान निर्माण एजेंसी ने कई पुल नये बनाये लेकिन कई पुलों को मरम्मत कर उसी पर नई सड़क बना दी, ठेकेदार द्वारा नई रेलिंग तक नही बनाई गई और पुरानी सीमेंट के खम्बो में बनी पुरानी रेलिंग को ही जस का तस रखा है ।

ग्राम करवड़ के पास इस प्रकार के गड्ढे बने हुवे सड़क पर।

ग्राम मोर के पास सड़क गम्भीर स्थिति में।

लाड़की और माही नदी पर स्थित भयावह

रतलाम-झाबुआ मार्ग पर पड़ने वाली दो बड़ी नदिया लाड़की और माही नदी है, जहां आज भी वर्षो पूर्व पुल निर्माण के साथ बनी रेलिंग ही बनी हुई है। सीमेंट के खम्बो से बनी रेलिंग के कई बड़े हिस्से गिर चुके हैं और ट्रक जैसे वाहन भी इस टूटी रेलिंग से सीधे नदी में गिर जाए। वाहनों की क्रासिंग के दौरान दुर्धटना का भय और बढ़ जाता है । एक दो स्थानों पर इट की पतली से दीवार बना कर माही नदी की रेलिंग को ठीक करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस के दूसरे हिस्से की रेलिंग कई स्थानों से टूट कर समाप्त हो गई है।

सड़क गड्डो में हुई तब्दील

पुलों की रेलिंग के साथ-साथ रतलाम-झाबुआ मार्ग पर कई स्थानों पर सड़क गड्डो में तब्दील हो चुकी है, अच्छी भली सड़क पर अचानक बड़े-बड़े गड्ढे ओर टूटी सड़क आने से वाहनों को भारी नुकसान हो रहा है। यहां ग्राम बामनिया के लाड़की नदी के बीच, ग्राम गोदड़िया के बाहर ग्राम करवड़ के बाहर से लेकर मुक्तिधाम तक, ग्राम मोर, घुघरी सहित रानीसिग तक कई गाँव के बाहर और आस-पास सड़क की पुरी तरह से टूट गई और सड़क गड्डो में तब्दील हो चुकी हैं। वाहन चालको की छोटी सी चूक बड़े हादसे को निमंत्रण देती दिख रही है। कुछ दिन पूर्व सड़क पर पड़े गड्डो को भरने का नाटक भी एमपीआरडीसी की ओर से किया गया और इक्का दुक्का जगह पिचिंग कर कार्य की इतिश्री कर ली। इधर बरसात की स्थिति में ये गड्ढे ओर जानलेवा हो चुके है जिनमे पानी भरे होने के कारण गड्डो की जानकारी तक नही हो पाती। ग्राम पंचायत करवड़ के सरपंच विकास गामड ने बताया कि रोड की स्थिति गम्भीर है और नगर रतलाम रोड स्थित नये स्कूल भवन के पास मार्ग की स्थिति गम्भीर है और आने जाने वाले स्कूली बच्चों और यहां से गुजरने वाले वाहनों पर दुर्धटना का खतरा बना रहता है, पूरे मार्ग को थोड़ी थोड़ी दूर पर बनाया गया हैं और कई जगह मार्ग को जर्जर हालत में छोड़ दिया गया है।

कछुवागति से चल रहा है कार्य

उक्त रतलाम-झाबुआ मार्ग को सरकार ने नवीन निर्माण के लिए स्वीकृत किया है और मार्ग की चौड़ाई बड़ा कर दस मीटर कर दी गई है। मार्ग का कार्य वर्तमान में थांदला से बामनिया मार्ग पर शुरू है, जो काफी धीमी गति से चल रहा है। निर्माण कार्य मे कोई खास तेजी नही होने से अभी लोगों को लंबे समय तक इस जर्जर मार्ग का ही उपयोग करना पड़ेगा। घुघरी निवासी वीरेंद्र बसेर ने कहा कि फिलहाल निर्माण एजेंसी और एमपीआरडीसी को मार्ग की रिपेयरिंग करना चाहिये जिससे मार्ग नया बने इससे पूर्व लोगो की यात्रा थोड़ा सुगम हो सके।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422